Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ●Wednesday, 10 December 2025 ●Year : 04 ●Issue : 322 ●Ranchi Edition ●Page : 12 ●Price : ₹3 ●www.thephotonnews.com E-Paper : epaper.thephotonnews.com

सुविचार

इस सभ्यता में पैदल आदमियों के संगठित समूह की कल्पना नहीं,भीड़ की कल्पना है।

-रघुवीर सहाय

Kritika Kamra Says It's A 'Privilege' To Be A Protagonist...

SHARE

सेंसेक्स	:	84,666.28
निफ्टी	:	25,839.65

SARAFA

सोना	:	12,075.00
चांदी	:	199.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

बिहार के वैशाली में बस-ऑटो की टक्कर तीन लोगों की मौत

PATNA : मंगलवार की सुबह बिहार के वैशाली जिले में हाजीपुर-लालगंज मुख्य मार्ग पर बस और ऑटो की आमने-सामने से टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सात की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार हाजीपुर-लालगंज राज्य मार्ग 74 पर धनुषी गांव के पास ऑटो और बस में सीधी टक्कर हो गई। ऑटो हाजीपुर से यात्री लोड कर लालगंज जा रही थी। इसी दौरान लालगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार बस से ऑटो की सामने से टक्कर हो गई । इस दुर्घटना में ऑटो सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हैं।

जापान में 7.5 तीव्रता का आया भूकंप, सुनामी की दो फीट ऊंची उठीं लहरें

TOKYO : उत्तरी जापान में सोमवार की देर रात 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके कारण 33 लोग घायल हो गए और प्रशांत महासागर के तटवर्ती इलाकों में सुनामी आ गई। दो फीट ऊंची लहरें उठने लगीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जापान सरकार भूकंप और सुनामी से हुए नुकसान का अब भी आकलन कर रही है। जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के सबसे उत्तरी प्रांत आओमोरी के तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में रात लगभग 11 बजकर 15 मिनट पर भूकंप आया था।

झारखंड पुलिस के आठ अधिकारियों को आईपीएस में प्रमोशन

RANCHI : झारखंड पुलिस सेवा के आठ पुलिस अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में प्रमोशन को लेकर गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह अधिसूचना भारतीय पुलिस सेवा प्रोन्नति अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है। जिन अधिकारियों को प्रोन्नति मिली है उनमें शिवेंद्र,राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, दीपक कुमार, मंजरुल होदा, राजेश कुमार.रोशन गुड़िया और श्रीराम समद शामिल हैं। इस प्रमोशन लिस्ट में शामिल तीन शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर और मुकेश कुमार महतो को फिलहाल प्रोविजनली शामिल किया गया है।

खंडित वैश्विक गठबंधनों के बीच भारत खुद तय करे विकास पथ : अडानी

दिग्गज उद्योगपति ने धनबाद स्थित आईआईटी-आईएसएम के 100वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम को किया संबोधित

- दुनिया भर के देश विशुद्ध रूप से अपने स्वार्थ के हिसाब से कर रहे हैं काम
- अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा प्रणालियों में देश को हासिल करनी चाहिए महारत
- सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश भारत को बता रहे कि कैसे करना चाहिए विकास

सपनों को हकीकत में बदलता है भारत

अडानी ने कहा कि भारत सपने नहीं बेचता, वह सपनों को हकीकत में बदलता है। उन्होंने 'कथात्मक उपनिवेशीकरण' को लेकर आगाह करते हुए कहा कि ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश अब यह बताना चाहते हैं कि भारत को किस प्रकार विकास करना चाहिए, जबकि भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन विश्व में सबसे कम है। उन्होंने वर्तमान युग को आर्थिक एवं संसाधन स्वतंत्रता के लिए भारत का 'दूसरा स्वतंत्रता संग्राम' बताते हुए कहा कि देश को बाहरी दबावों के कारण अपनी आकांक्षाओं को अमान्य नहीं करना चाहिए।

50% भुगतान वाली वार्षिक इंटर्नशिप की घोषणा

अडानी ने कहा कि आईआईटी (आईएसएम), धनबाद की स्थापना के साथ एक राष्ट्रीय दूरदर्शिता का जन्म हुआ था। एक सदी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के दौरान भी खनन एवं भूविज्ञान में भारत की क्षमताओं को विकसित करने के लिए इस संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी। अडानी ने आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए 50% भुगतान वाली वार्षिक इंटर्नशिप और संस्थान में अडानी 3-एस खनन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की भी घोषणा की। अदाणी ने छात्रों से आग्रह किया कि वे निडर होकर सपने देखें, अथक परिश्रम करें। नवाचार को अपनाएं तथा भारत की संप्रभु क्षमताओं का निर्माण करने वाले मूल के संरक्षक बनकर एक आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद करें।

DHANBAD @ PTI : मंगलवार को अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की संप्रभुता उसकी धरती में मौजूद संसाधनों पर नियंत्रण करने पर निर्भर करती है। देश को खंडित वैश्विक गठबंधनों के बीच अपना विकास पथ खुद तय करना होगा। अडानी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस), धनबाद के 100वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भर के देश विशुद्ध रूप से अपने स्वार्थ के हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसे में भारत को अपनी वृद्धि को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा प्रणालियों में महारत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 21वीं सदी में भारत की संप्रभुता, देश के प्राकृतिक संसाधनों एवं ऊर्जा प्रणालियों पर उसके नियंत्रण पर निर्भर करेगी। भारत को एक ऐसे विश्व में, जहां राष्ट्रीय आत्म-संरक्षण और वैश्विक गठबंधनों में दरार बढ़ती जा रही है, अपना विकास पथ तैयार करना होगा। अडानी ने कहा कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, तो उसका मकसद केवल इमारतों को नष्ट करना या पांडुलिपियों को आग लगाना नहीं था। उन्होंने कहा, उसका असली निशाना हमारी सभ्यता के आत्मविश्वास, हमारी ज्ञान प्रणालियां और विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से सोचने की हमारी क्षमता थी। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो सभ्यता यह भूल जाती है कि उसे कैसे तोड़ा गया, वह उठना भी भूल जाती है। अडानी ने कहा, सदियों बाद, जब अंग्रेज पहले से ही कमजोर भारत में आए, तो उन्होंने ज्ञान को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपने हिसाब से बदला।

लोकसभा में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया दावा

आरएसएस के 'प्रोजेक्ट' के तहत संस्थाओं पर किया गया कब्जा

सीईसी और ईसी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने पर उठाए सवाल

- दिसंबर 2023 में बदल गया कानून, ताकि किसी चुनाव आयुक्त को नहीं किया जा सके दंडित
- देश के अब तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया इस तरह का काम
- वोट का ही मतलब नहीं रहेगा, तो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत का संभव नहीं अस्तित्व
- संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- निर्धारित विषय पर बोलें नेता प्रतिपक्ष

'वोट चोरी' सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी कृत्य

राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि 'वोट चोरी' सबसे बड़ा 'राष्ट्र विरोधी' कृत्य है। भूमि आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं। यह 'आइडिया ऑफ इंडिया' को नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह वर्ण व्यवस्था में यकीन करते हैं और इस क्रम में खुद को सबसे ऊपर मानते हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि देश 1.5 अरब लोगों का तानाबाना है, जो वोट के माध्यम से बुना हुआ है।

जांच एजेंसियों पर कब्जा करने का था लक्ष्य

राहुल गांधी के इस दावे पर सत्तापक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को निर्धारित विषय पर बोलना चाहिए। जवाब देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह विषय वोट से जुड़ा है और वह इसी आधार पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद जांच एजेंसियों पर कब्जा करने का लक्ष्य था। उन्होंने दावा किया कि निर्वाचन आयोग पर कब्जा किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि निर्वाचन आयोग सत्तापक्ष में बैठे लोगों के साथ मिलीभगत करके फैसले कर रहा है और किसी भी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार प्रचार के लिए लंबी अवधि रखी जाती है।

देश रोहिंग्या, बांग्लादेशियों के लिए नहीं एसआईआर जरूरी : संजय जायसवाल

NEW DELHI : लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरूआत सत्ता पक्ष की ओर से पश्चिम चंपारण से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संजय जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि यह देश रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए नहीं है और ऐसे में देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया जरूरी है। मतदाता सूची को अपडेट करने से जुड़ी एसआईआर का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 35 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरे इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में घुसपैठिए थे। जयसवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल का भी स्वागत किया और कहा कि विपक्षी सदस्य भले ही कहें लेकिन, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है।

NEW DELHI @ PTI : मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के 'प्रोजेक्ट' के तहत विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचन आयोग पर कब्जा करना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वाली चयन समिति में प्रधान न्यायाधीश को शामिल क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने दिसंबर 2023 में कानून बदल दिया, ताकि किसी चुनाव आयुक्त को उसके फैसलों के लिए दंडित नहीं किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया।

राहुल गांधी ने कहा कि अगर वोट का ही मतलब नहीं रह जाएगा तो लोकसभा, विधानसभा या पंचायत, किसी का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। कांग्रेस नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इनके 'प्रोजेक्ट' का अगला हिस्सा भारत के संस्थागत ढांचे पर कब्जा करने का था। उन्होंने दावा किया, आरएसएस ने एक-एक करके संस्थाओं पर कब्जा शुरू कर दिया। सब लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति कैसे होती है।

देश के लोगों की जिंदगी को आसान बनाना तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकता : पीएम मोदी

- राजग संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को किया संबोधित
- सामान्य जन की सुविधा के वास्ते होने चाहिए कानून, असुविधा के लिए नहीं
- रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर में तेजी से बढ़ रहा भारत, स्पष्ट मंशा के साथ हो रहे सुधार

NEW DELHI @ PTI : मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्राथमिकता देश के लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि कानून या नियम सामान्य जन की सुविधा के लिए होने चाहिए और उनकी वजह से किसी निर्दोष भारतीय को असुविधा नहीं होनी चाहिए। देश अब पूरी तरह रिफॉर्म एक्सप्रेस के दौर में है, जहां सुधार तेजी से और स्पष्ट मंशा के साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के सुधार सिर्फ अर्थव्यवस्था या राजस्व पर केंद्रित नहीं है, ये पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि सरकार का लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की परेशानियां दूर करना है, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें।

सांसदों को पीएम ने दिए दिशा-निर्देश

बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को बहुत अच्छे दिशा-निर्देश दिए और यह संदेश दिया कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा मुद्दा रिफॉर्म एक्सप्रेस है। इस बैठक में राजग के सभी सांसद शामिल हुए। रिजिजू ने कहा, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मोदी सरकार की रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है और अब यह रुकेगी नहीं। यह सुधार देश के हर नागरिक की जिंदगी बदलने के लिए है। जब हम सुधार की बात करते हैं, तो कुछ लोग इसे आर्थिक सुधार समझते हैं, कुछ राजनीतिक, कुछ प्रशासनिक या सांस्कृतिक सुधार। लेकिन सुधार का असली मतलब है-हर नागरिक के जीवन में बेहतरी है।

'जालसाजी' संबंधी याचिका पर सोनिया गांधी को नोटिस

AGENCY NEW DELHI : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और पुलिस से मतदाता सूची में जालसाजी से नाम शामिल किए जाने के आरोपों वाली याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें इस आरोप की जांच से इनकार कर दिया गया था कि 1983 में भारतीय नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने मजिस्ट्रेट अदालत के 11 सितंबर के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मजिस्ट्रेट अदालत ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि शिकायत के आरोप अपर्याप्त तथ्य वाले और इस मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए, न्यायाधीश गोगने ने मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी के लिए सूचीबद्ध की।

इंडिगो की उड़ानों में सरकार ने कर दी पांच प्रतिशत की कटौती

AGENCY MUMBAI : मंगलवार को विमानन नियामक डीजीसीए ने परिचालन संकट से गुजर रही एयरलाइन इंडिगो को सर्दियों के दौरान अधिक मांग वाले मार्गों पर नियोजित उड़ानों में पांच प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की सेवाओं को सुव्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। कड़े सुरक्षा नियमों के लिए योजना बनाने में नाकाम रहने की वजह से इंडिगो को देश भर में हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। मंगलवार को भी इंडिगो ने 6 हवाईअड्डों से 422 उड़ानों को रद्द किया। डीजीसीए ने आठ दिसंबर के अपने आदेश में इंडिगो को बुधवार तक संशोधित उड़ान कार्यक्रम प्रस्तुत करने को कहा।

- विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कड़ी कार्रवाई का दिलाया भरोसा

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बोले- किसी विभाग में पैसे की कमी नहीं

विधानसभा में 7721.25 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पास

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में ध्वनिमत से 7721.25 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का सदन में जवाब शुरू होते ही बीजेपी ने वॉकआउट किया। वित्त मंत्री ने कहा कि एक अप्रैल से 30 नवंबर तक 67,696.37 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हुई, जिसमें 66,871 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कुल 98.8 फीसद खर्च किया गया है। स्टेट ऑन टैक्स के लिए टारगेट 41600 करोड़ रुपये का था, जिसमें 30 नवंबर तक 23,897 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। वहीं स्टेट टैक्स से 19456 करोड़ वसूली का लक्ष्य है, जिसमें 8565.63 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है। हम आंतरिक संसाधन को मजबूत कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 30 नवंबर तक केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में 47040 करोड़ में से 30971 करोड़ रुपये ही मिले हैं। वहीं केंद्रीय अनुदान में 17057 करोड़ में 4261.70 करोड़ ही मिले हैं।

केंद्र पैसा देता तो 450 रुपये में देते गैस सिलेंडर : वित्त मंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार पैसे देती को 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी देते। उज्जवला गैस योजना के तहत 65 लाख लाभुक हैं।

- मंत्री का जवाब शुरू होते ही सदन से वॉकआउट कर गए भाजपा के विधायक

विधानसभा में धान के एमएसपी और विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा

RANCHI : मंगलवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा परिसर में भी सरकार विरोधी नारे लगते रहे। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायक विधि व्यवस्था और धान के समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर सरकार पर निशाना साधते दिखे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार द्वारा इस साल घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये को नाकाफी बताते हुए किसानों से वादाखिलाफी का आरोप लगाया। सदन में प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल काउंसलिंग में हो रही घपलेबाजी का मामला उठाया। उन्होंने सदन से मांग की कि झारखंड संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पोर्टल को एनपीए के पोर्टल के साथ लिंक किया जाए।

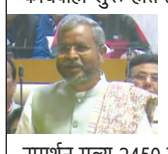

जयराम महतो ने सरकार पर किया प्रहार

झारखंड विधानसभा के अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक जयराम महतो ने राज्य में छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्रों की स्थिति को उठाते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दो-दो साल से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे युवा हताश हैं, जबकि विधायक 4.32 करोड़ रुपये की लागत से बने आलीशान आवास में रहने जा रहे हैं। इसे उन्होंने राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कारर दिया। महतो ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार एक-दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं, लेकिन इसकी कीमत छात्रों को नहीं चुकानी चाहिए। उन्होंने छात्रवृत्ति भुगतान तुरंत सुनिश्चित करने की मांग की, इसे आने वाली पीढ़ी के साथ अन्याय करार दिया। विधायक ने अधिकारियों की जवाबदेही पर भी कड़ी नाराजगी जताई।

सेहत की सुरक्षा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्टडी का बनाया प्लान

महिलाओं में थायरॉयड विकार से निजात की होगी व्यवस्था

PHOTON NEWS, RESEARCH DESK : मानव शरीर के भीतर विभिन्न कारणों से रह-रहकर स्वास्थ्य संबंधी विकार की स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति के निदान के लिए लगातार रिसर्च होते रहते हैं। शरीर के भीतर हमेशा होने वाली जैविक क्रियाओं में असंतुलन के कारण स्वास्थ्य विकार पैदा होते हैं। ऐसे विकारों में थायरॉयड आज के समय आम विकार बन गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों के अनुसार, शरीर में आयोडीन और थायरॉयड हार्मोन की कमी या अधिकता की स्थिति में यह विकार पैदा होता है। कमी होने पर इसे हाइपोथायरॉयडिज्म और अधिकता होने पर हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यह स्थिति महिला या पुरुष किसी में भी हो सकती है, लेकिन महिलाओं में यह आम है और गर्भावस्था के दौरान इसकी स्थिति अधिक बनती है। इस स्थिति से निपटने के लिए और महिलाओं को इससे निजात दिलाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने हाल ही में बड़ी पहल की है। आईसीएमआर की ओर से गर्भवती महिलाओं में थायरॉयड विकारों पर जल्द ही राष्ट्रीय अध्ययन शुरू करने का प्लान बनाया गया है। इस अध्ययन को शुरू करने से पहले देशभर के सभी शोध संस्थानों और अस्पतालों से डेटा मांगे गए हैं। आईसीएमआर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. तानिका लिंगदोह ने बताया कि भारत में गर्भावस्था के दौरान थायरॉयड विकार एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है।

व्यापक स्तर पर जानकारी हासिल करने के लिए शोध संस्थानों से मांगे गए हैं डेटा

- कारणों और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने की तैयार होगी वैज्ञानिक प्रक्रिया
- गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिल स्थितियों का किया जाएगा गंभीर विश्लेषण
- प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में सबसे आम अंत:स्रावी विकारों में एक है यह बीमारी
- प्रेग्नेंसी के समय शरीर में बढ़ जाती है आयोडीन और थायरॉयड हार्मोन की डिमांड

- मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए साक्ष्य आधारित नीति बनाएगा आईसीएमआर

समय पूर्व प्रसव और बच्चे का बौद्धिक विकास

लिंगदोह के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान थायरॉयड विकारों के वास्तविक बोझ, कारणों और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने के लिए राष्ट्रीय अध्ययन की योजना है, जिसके लिए सभी संस्थान अपने यहां पंजीकृत गर्भवती महिलाओं में हाइपोथायरॉयडिज्म का डेटा साझा करना। इस अध्ययन के आधार पर आईसीएमआर मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य के लिए साक्ष्य आधारित नीति बनाएगा।

चार बिंदुओं पर केंद्रित होगी स्टडी तय किए जाएंगे मानक

लिंगदोह का कहना है कि यह पहल गर्भवती महिलाओं में थायरॉयड विकारों की सटीक प्रचलन दर, जोखिम कारक और स्वास्थ्य परिणामों को समझने में मदद करेगी। इसके तहत देशभर से चल रहे या पूरे हो चुके प्रेगनेंसी कोहॉर्ट स्टडी, क्रॉस-सेक्शनल सर्वे और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स से डेटा मांगा गया है। यह अध्ययन चार बिंदुओं पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान हाइपोथाइरॉयडिज्म का आकलन करना है।

डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुआ रिटायर्ड बैंक कर्मी, उड़ा लिए 51 लाख रुपये

वीडियो कॉल पर दंपती को घर में ही बना लिया था बंधक, मनी लांड्रिंग का भी दिया झांसा

PHOTON NEWS KODERMA : अब देश भर के साथ यहां के लोग डिजिटल अरेस्ट के भी शिकार हो रहे हैं। मनी लांड्रिंग का हवाला देकर कोडरमा थाना क्षेत्र निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी सुरेश प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी से 51 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस, सीबीआई अधिकारी और कोर्ट से जुड़ा अधिकारी बताते हुए पति-पत्नी को वीडियोकॉल के जरिए दो दिनों तक कथित रूप से डिजिटल अरेस्ट में रखा। इसके बाद बैंक खातों, एफडी, गोल्ड, शेयर समेत तमाम वित्तीय जानकारी लेकर मध्य प्रदेश के एक खाते में 51 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। तीन दिन बाद पीड़ित दंपती कोडरमा थाना पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराया।

पीड़ित सुरेश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सबसे पहले उन्हें एक महिला ने फोन कर कहा कि उनके आधार से नया मोबाइल नंबर जोड़ा गया है। यही नहीं, उसी नंबर से एक बैंक खाता खोला गया है, जिससे अवैध लेन-देन किया गया है।

पीड़ित सुरेश प्रसाद गुप्ता

इसके बाद तीन अलग-अलग नंबरों से भी फोन आया और ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस और सीबीआई का अधिकारी बताया। हम दोनों पति-पत्नी को लगातार वीडियोकॉल पर रखा गया। इस बीच उन्होंने किसी से बात नहीं करने की चेतावनी दी और यह भी धमकी दी कि मोबाइल फोन बंद नहीं करना है।

ठगों ने कहा कि सीबीआई के एसपी और दिल्ली पुलिस के अधिकारी तुमलोगों की अवैध लेन-देन में संलिप्तता की जांच कर रहे हैं। इस तरह से हमें हाउस अरेस्ट पर रखा गया।

फर्जी जज, फर्जी कोर्ट और गिरफ्तारी का डर : इस बीच 2 दिसंबर की सुबह ठगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कराया और कथित तौर पर सीबीआई कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया।

फर्जी कोर्ट में पति-पत्नी पर मनी लांड्रिंग के आरोप बताए गए और कैश, एफडी, गोल्ड व शेयर की जानकारी मांगी गई। आदेश का पालन नहीं करने पर गिरफ्तारी और वारंट जारी करने की धमकी दी गई। पति-पत्नी ने डर के मारे अपनी सभी एफडी तोड़ कर बैंक खाते में जमा करा दी। इसके बाद ठगों के कहने पर 51 लाख रुपये मध्य प्रदेश के सेंधवा स्थित एक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए, जिसका नाम पतिमो पीएम एस्टेट्स एलएलपी बताया गया।

जागरूकता से ही हो सकता बचाव : एसपी

कोडरमा के एसपी अनुदीप सिंह ने कहा कि जिले में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, यह अफसोस की बात है। साइबर ठग लॉटरी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी नौकरी ऑफर जैसे नए-नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अपने बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें। अनजान लिंक, ई-मेल या एप तुरंत डिलीट करें। किसी भी प्रकार की ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि नुकसान रोकने की संभावना बनी रहे।

दहेज नहीं मिला तो प्रेमी ने वायरल की फोटो, पहुंचा जेल

पत्रकारों को मामले की जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना अंतर्गत एक पीड़िता से सोशल मीडिया पर शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी मो. शमसेर अली उर्फ मो. शमसेर आलम गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने लॉकडाउन के समय से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और वाट्सएप के माध्यम से उसके साथ बातचीत शुरू की थी। उसने शादी का वादा किया और दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। लेकिन, जब पीड़िता के परिवार ने दहेज देने से मना किया, तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और उसके आपत्तिजनक फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत कासमा थाना क्षेत्र के विसम्भरपुर के स्कूली गांव से गिरफ्तार किया। उसके पास से पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो वाला स्मार्टफोन भी बरामद किया गया है।

BRIEF NEWS

मोबाइल छिनतई का आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

LATEHAR : महुआडांड़ थाना की पुलिस ने मोबाइल छिनतई के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। 19 वर्षीय आकिब अली नामक युवक गुड़गुटोली का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक राहगीर का मोबाइल फोन छीन लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आकिब अली को पकड़ लिया। उसे न्यायिक हिरासत में लातेहार मंडल कारा भेज दिया गया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि इस घटना में दो अन्य युवक भी शामिल थे, जिनकी पहचान जरहाटोली निवासी साहिल उर्फ चिल्ड और अंबवाटोली निवासी खलील अंसारी के रूप में हुई है। दोनों फरार हैं। पुलिस जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लेगी।

सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे भू-माफिया

RAMGARH : जिले में भू माफिया काफी सक्रिय हो गए हैं। भू माफिया अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर उनके पीठ पीछे सरकारी जमीन पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास कर रहे हैं। समाहरणालय के समीप छत्तरमांडू में वात्सल्य धाम के सामने ऐसे ही एक गैर मजरूर जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था। अंचल अधिकारी रमेश रविदास को जैसे ही भू-माफियाओं की हरकतों का पता चला उन्होंने कार्रवाई की। सबसे पहले उन्होंने जीएम लैंड पर चलाए जा रहे जेसीबी का काम रुकवाया। इसके बाद दस्तावेजों की मांग की। साथ ही जांच पूरी होने तक किसी भी प्रकार का काम नहीं करने का आदेश दिया।

बिरसा कॉलेज में पीजी के बैच को दी गई विदाई

KHUNTI : बिरसा कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग में मंगलवार को स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सेमेस्टर के छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। जितेंद्र, मनीष, अनामिका, स्मृति, मनीषा, प्रतिभा, फूलमनी सहित कई छात्रों ने शानदार नृत्य और गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान विदाई लेने वाले छात्रों ने कॉलेज में बिताए अनमोल पलों को याद कर अपने अनुभव साझा किया। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य प्रो सीके भगत ने छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की बधाई देते हुए कहा कि कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। वहीं विभाग के राजकुमार गुप्ता ने छात्रों को सामाजिक दायित्व निभाने और निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित किया। विभागाध्यक्ष प्रो जया भारती कुजूर ने पूर्व छात्रों के रूप में कॉलेज से जुड़े रहने का आग्रह करते हुए भविष्य के लिए बधाई दी। इस मौके पर स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के रूप में दीक्षा कुमारी और प्रमोद महतो को सम्मानित किया गया। दीक्षा को कॉलेज के लिए कई बार विश्वविद्यालय स्तर पर पुरस्कार दिलाने की उपलब्धि पर और प्रमोद को अनुशासन और विभागीय गतिविधियों में सक्रिय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया।

डीसी ने की पर्यटन व खेल के कार्यों की समीक्षा

RAMGARH : जिला एवं प्रखंड स्तर पर इनडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। जिला खेल पदाधिकारी पर्यटन विकास और खेल विकास को ध्यान में रखकर तत्परता दिखाएं। वे स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अंचल अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करें। यह बातें मंगलवार को डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने पर्यटन विकास एवं जिला खेल कार्यालय की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान कही। बैठक के दौरान जिला खेल पदाधिकारी संजीत कुमार ने डीसी को बताया कि विभागीय स्तर से जिला और प्रखंड स्तर पर इनडोर एवं आउटडोर स्टेडियम निर्माण किया जाना है।

केंदुआडीह में गैस रिसाव जारी असुरक्षित क्षेत्र का लगा नोटिस

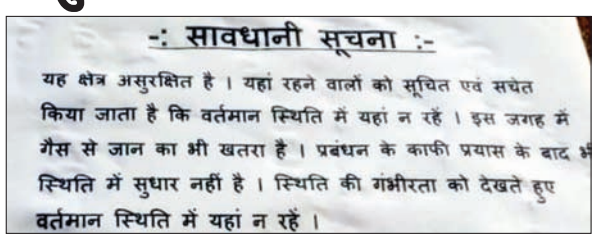

DHANBAD : केंदुआडीह की राजपूत बस्ती और आसपास के इलाके में जहरीली गैस का रिसाव बंद नहीं हुआ है। इसी बीच बीसीसीएल प्रबंधन ने क्षेत्र में असुरक्षित क्षेत्र का नोटिस लगा दिया है। इसके माध्यम से लोगों को सचेत किया गया है कि वे जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें, लेकिन कुछ लोग अब भी यहां से जाने के लिए राजी नहीं हैं। बीसीसीएल के पुटकी-बलियाडीह क्षेत्र के केंदुआडीह कोलियरी प्रबंधन के उस नोटिस से बताया है कि गैस रिसाव रोकने को लेकर बीसीसीएल के सारे कार्य विफल हैं और अब एकमात्र विकल्प यहां से लोगों को हटाना है। बीसीसीएल प्रबंधन के इस नोटिस के बाद से लोगों में और अधिक आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजपूत बस्ती निवासी सदानंद बोस ने कहा कि हम हटने को तैयार हैं, लेकिन प्रबंधन आरआर पॉलिसी के तहत उन्हें विस्थापित करे और पुनर्वास की व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि सिर्फ डर दिखाकर प्रबंधन किसी को नहीं हटा सकती है।

संत जोसेफ स्कूल में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

KHUNTI : जिले के तोरपा प्रखंड के कामडा स्थित संत जोसेफ क्लासंस स्कूल में मंगलवार को गूंज संस्था और संभव ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में सामाजिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कक्षा दो से पांचवीं तक के विद्यार्थियों को रीसायकल्ड कपड़े से बने स्कूल किट-बैग और पुनः उपयोग की गई नोटबुक वितरित की गईं। यह पहल बच्चों को सतत जीवनशैली अपनाने और संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का सार्थक प्रयास है। विद्यालय परिसर में हाल ही में अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता से किचन गार्डन भी विकसित किया गया है। इस माध्यम से ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चों को विद्यालय में ही स्वच्छ, ताजा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

दिव्यांग बच्चों के बीच पहुंचे अडानी 'नई उड़ान कैफे' का किया उद्घाटन

PHOTON NEWS DHANBAD : झारखंड के धनबाद में स्थित पहला कदम स्कूल और नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट दिव्यांग बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। दिव्यांग बच्चों के जीवन को संवारने के लिए इन संस्थानों को अब गौतम अडानी का साथ मिला है। अडानी समूह के चेयरमैन और दुनिया के जानेमाने उद्योगपति गौतम अडानी ने धनबाद में नारायणी चैरिटेबल ट्रस्ट और 'पहला कदम स्कूल' जाकर दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे काम को सराहा और मदद का संकल्प लिया। उन्होंने इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से विकसित 'नयी उड़ान कैफे' का उद्घाटन किया। इस कैफे का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को खाने-पीने के समान बनाने के लिए वोकैशनल ट्रेनिंग प्रदान करना है,

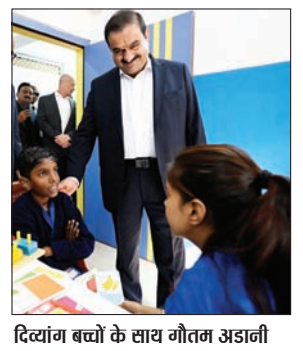
दिव्यांग बच्चों के साथ गौतम अडानी

ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। इस मौके पर गौतम अडानी ने दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी में सहयोग देने का संकल्प लिया। उन्होंने अगले 3 साल तक संस्थान को लगातार सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई।

मिलेगी सपनों को उड़ान : 'नयी उड़ान कैफे' में दिव्यांग बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे कैफे संचालन, खाना बनाने, सर्विंग, और अन्य संबंधित कौशल सीख सकें। यह प्रोग्राम बच्चों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देगा। पहला कदम स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। स्कूल न सिर्फ विशेष शिक्षा, बल्कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल, और स्वास्थ्य सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराता है। यहां के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की पैरा-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। गौतम अडानी ने दिव्यांग बच्चों से बातचीत की और उनकी भावनाओं को सुना। बच्चों ने उत्साह के साथ अपने अनुभव और उम्मीदें उनके साथ साझा की।

मेदिनीनगर नगर निगम कर्मियों ने की भूख हड़ताल, दिया धरना

अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन करते नगर निगम कर्मी

AGENCY PALAMU : मेदिनीनगर नगर निगम के कर्मचारियों ने मंगलवार को अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर निगम परिसर में एक दिवसीय भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन झारखंड लोकल बॉडीज इम्प्लॉइज फेडरेशन के बैनर तले आयोजित किया गया। कर्मचारियों की पांच प्रमुख मांगों में दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का नियमितीकरण, वेतन संरचना में सुधार, सेवा शर्तों में स्पष्टता और व्यवहारिकता, पदोन्नति नीति लागू करना और कार्यस्थल पर सुविधाओं में बढ़ोतरी करना शामिल है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कर्मचारियों ने बताया कि वे शहर की साफ-सफाई, जल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और अन्य नगर निगम सेवाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं, परंतु उन्हें उचित वेतन व सुरक्षा नहीं मिल रही है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते नगर निगम का सामान्य कामकाज ठप हो गया। विभिन्न विभागों में काम बंद रहने से कार्यालय में पहुंचे लोगों को वापस लौटना पड़ा। बंद काउंटरों और अनुपस्थित अधिकारियों के कारण आम नागरिकों को सेवाओं से वंचित होना पड़ा। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विशुन राम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द समाधान नहीं निकालती है तो वे कार्य बहिष्कार और अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे।

चलती ट्रेन के सामने कूदा युवक, मौत

GIRIDIH : झारखंड के गिरिडीह जिले के पचम्बा उप नगर थाना इलाके के हरीचक में मंगलवार की सुबह पटरी पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान प्रकाश दास (30) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक ने गिरिडीह-कोडरमा रेलखंड में चलती ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दी है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के पिता टूपलाल दास और पत्नी अपने बच्चों के साथ मौके पर पहुंची । देखा कि प्रकाश का शव पटरी पर पड़ा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद घटनास्थल पर पचम्बा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान क्यों दी है इसके कारणों का अबतक पता नहीं चल पाया है । इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है हालांकि चर्चा है कि घर में संपत्ति बंटवारे को लेकर कुछ विवाद हुआ था आंशका है कि इसी से नाराज होकर युवक ने यह कदम उठाया है। प्रकाश की मौत के बाद पूरा परिवार गमगीन है।

खूंटी में आठवीं की छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

KHUNTI : सदर थाना के सामने स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (बालिका) में पढ़ने वाली आठवीं कक्षा की छात्रा फुलमनी नाग ने मंगलवार को फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फुलमनी मूल रूप से अड़की प्रखंड की बिरबांकी पंचायत के इचाकुटी गांव की रहने वाली थी। उसके पिता जीवन नाग खूंटी के अमृतपुर मोहल्ले में चम्पक कुम्हार के मकान में किराये पर रहते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। फुलमनी ने इसी किराये के घर में फांसी लगा ली। मामले के संबंध में सांसद प्रतिनिधि पीटर मुंडू ने परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने बताया कि फुलमनी पिछले 22-23 नवंबर से स्कूल नहीं जा रही थी और अक्सर गुमसुम रहती थी। एक दिन उसकी बहन ने उससे कहा था कि यदि स्कूल जाना है तो जाओ, अन्यथा गांव लौट जाओ। मंगलवार को जब उसके भाई-बहन स्कूल से लौटे, तो उन्होंने देखा कि फुलमनी का शव घर में फंदे से लटका हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया।

ज्योतिष गणना 28 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व कोहरे का रहेगा प्रकोप, सताएगी महंगाई

16 दिसंबर से शुरू होगा खरमास, एक महीने तक नहीं होंगे मांगलिक कार्य

AGENCY CHATRA : हिंदू धर्म में खरमास के महीने को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। पंडित सचिन पांडेय ने बताया कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य देव धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस काल को खरमास या मलमास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। साल 2025 में खरमास की शुरूआत 16 दिसंबर से होने वाली है, जिससे शादी-विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे सभी शुभ कार्यों पर एक महीने के लिए रोक लग जाएगी। पंचांग के अनुसार, सूर्य देव 16 दिसंबर 2025 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास की शुरूआत हो जाएगी। यानी पूरे एक महीने तक मांगलिक कार्यों के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा और फिर से शुभ कार्य शुरू किए जा सकेंगे। इस संबंध में आचार्य चेतन पांडे ने बताया कि पौष मास हिंदू पंचांग का दसवां महीना होता है। इसकी शुरूआत मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से होती है।

इस बार पौष महीने की शुरूआत 5 दिसंबर दिन शुक्रवार से हुआ है। इसे पूष का महीना भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान पितरों की शांति के लिए दान और सेवा विशेष फलदायी माना जाता है। यह महीना विशेष रुप से सूर्य देव से जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान सूर्यदेव की आराधना के लिए इसे अत्यंत पवित्र माना गया है।

पौष माह में सूर्य उपासना करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में भागवत कथा, रामायण पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जप व अन्य वैदिक मंत्रों का जप-तप और सत्संग करने से पाप क्षय होता है। पौष माह में कई प्रमुख व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। इसमें सफला एकादशी, संकष्टी चतुर्थी, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और पौष अमावस्या विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर पितरों का श्राद्ध, तर्पण और दान करना शुभ माना गया है। इससे पितृ दोष दूर होता है और जीवन की परेशानियां कम होती हैं।

इस साल पौष माह 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार से शुरू हुआ है और इसकी समाप्ति 3 जनवरी 2026 शनिवार को होगी। पौष महीना इस बार पूरे 30 दिनों का होगा। हालांकि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि 2 दिन रहेगा, जबकि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन भोग करेगा। पौष महीने में यत्र-तत्र वर्षा होगी। इस महीने पांच शुक्रवार शुभ फलकारक हैं। धनु राशि की सूर्य संक्रांति मंगलवारी है।

ऐसे में किराना की वस्तुओं में महंगाई बढ़ेगी। 28 दिसम्बर से लेकर 14 जनवरी के आसपास ओला, पत्थर, बेमौसम बारिश और कोहरा से जनजीवन प्रभावित होगा।

पौष माह में क्या करें - क्या नहीं करें

पौष आध्यात्मिक रुप से जप-तप का मास है। इसलिए इस अवधि में मांसाहार और शराब का सेवन पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। इस अवधि में बैंगन, मसूर की दाल, कोहड़ा, मुली, जैसे भोजन का सेवन अशुभ माना जाता है। इनसे परहेज करना चाहिए। पौष मास में ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही और शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना उत्तम माना जाता है। तामसिक और भारी भोजन से दूरी रहें। इस अवधि में तप, जप और साधना करें। विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य इस महीने नहीं किए जाते हैं। यह अवधि आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष शुभ माना जाता है। वहीं 5 दिसंबर दिन शुक्रवार से पौष महीने का भले ही शुरूआत हो रही है, लेकिन खरमास 16 दिसंबर से शुरू होगा। खरमास धनु की संक्रांति में लगता है। यह एक महीने तक चलता है। इस बार धनु की संक्रांति 16 दिसंबर दिन मंगलवार को है। 2026 में 14 जनवरी दिन बुधवार की रात में भगवान सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पूरे 1 महीने के बाद एक बार फिर से शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे।

BRIEF NEWS

रोटरी क्लब ऑफ रांची ने समागम में मुख्यमंत्री को किया आमंत्रित

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मंगलवार को रोटरी क्लब ऑफ रांची के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के क्रम में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस समागम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। यह कांफ्रेंस 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल, अनिल सिंह, रेखा सिंह तथा रश्मि अग्रवाल शामिल थे। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने का आश्वासन दिया। उन्होंने रोटरी क्लब के सदस्यों को आगामी तीन दिवसीय सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी।

23 जनवरी को पहाड़ी मंदिर में होगा भोले बाबा का तिलकोत्सव

RANCHI : रांची पहाड़ी बाबा का तिलकोत्सव 23 जनवरी को मनाया जाएगा। शिव भक्तों की ओर से पहाड़ी बाबा को नेगचार के साथ तिलक चढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम पहाड़ी मंदिर में सुबह आठ बजे से शुरू होगा। महोत्सव के बाद श्रद्धालुओं के बीच भंडारा का वितरण होगा। वहीं, शाम साढ़े सात बजे से महाआरती होगी। इससे पहले 20 जनवरी को सुबह 11 बजे से महामंत्रों के जाप के साथ पहाड़ी बाबा का महारुद्राभिषेक अनुष्ठान होगा।

अवैध हथियार रखने के मामले में 4 लोगों को 10 साल की सजा

RANCHI : अवैध हथियार रखने के गंभीर मामले में न्यायालय ने 1 महिला समेत चार आरोपियों को 10-10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं। सभी पर अलग-अलग धाराओं में कुल 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक आरोपी को 6-6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 26 मार्च 2018 को कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में नबील अख्तर, मुबारक अंसारी, जाहिर अंसारी और रजिया खातून को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपी हिंदपीढ़ी निवासी मुस्ताक के घर में किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने घर में तलाशी ली, जिसमें एक बोरा में रखा 1 एके-47, 3 मैगजीन, 6 देशी पिस्तौल, 56 जिंदा कारतूस और 250-250 ग्राम के दो थैले विस्फोटक सामान बरामद किया गया था।

झारखंड में खेल के क्षेत्र में मौजूद हैं अपार संभावनाएं : हेमंत सोरेन

चैंपियन बनने के बाद मुख्यमंत्री से झारखंड की अंडर-14 फुटबॉल टीम ने की मुलाकात

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को झारखंड विधानसभा में झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने टीम के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगियों को राष्ट्रीय चैंपियन बनने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खेल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

सरकार की खेल नीतियों से युवाओं को मिल रही प्रेरणा

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के युवाओं की प्रतिभा और समर्पण झारखंड के गौरव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह उम्मीद जताई कि इसी प्रकार झारखंड के खिलाड़ी भविष्य में भी खेल जगत में नए आयाम स्थापित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के उमरिया में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित 69वीं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड की अंडर-14 बालक फुटबॉल टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। फाइनल मुकाबले में झारखंड ने रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में पंजाब को 6-5 से पराजित कर यह गौरव हासिल किया। यह प्रतियोगिता झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के बैनर तले आयोजित हुई थी। खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान बताया कि राज्य सरकार की खेल नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं से उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रेरणा मिल रही है।

झारखंड की अंडर-14 फुटबॉल टीम से मुलाकात करते सीएम हेमंत सोरेन

सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करता भारतीय खो-खो महासंघ का प्रतिनिधिमंडल

मार्च में आयोजित की जाएगी प्रथम कॉमनवेल्थ खो-खो प्रतियोगिता

मुख्यमंत्री से विधानसभा में भारतीय खो-खो महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर कॉमनवेल्थ खो-खो महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष आगामी 9 से 14 मार्च 2026 तक रांची में आयोजित होने वाली प्रथम कॉमनवेल्थ खो-खो प्रतियोगिता के आयोजन संबंधी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बता दें कि 2026 में झारखंड को एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी मिलने जा रही है। यह प्रतियोगिता झारखंड की धरती पर आयोजित होने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय खो-खो स्पर्धा होगी। जिसमें 23 देशों के बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कॉमनवेल्थ खो-खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल, अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सचिव एमएस त्यागी और महासचिव उपकार सिंह विरक शामिल थे। राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों में विधायक और झारखंड राज्य खो-खो संघ के महासचिव मथुरा प्रसाद महतो, संरक्षक विधायक सीपी सिंह, संघ के चेयरमैन संतोष प्रसाद, महासचिव नवीन कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष विनय कुमार जायसवाल, समेत अन्य मौजूद थे।

एक्शन के विरोध में सुबह से शाम तक मैदान में जमे रहे लोग

रिम्स कैंपस में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, फिर चला बुलडोजर

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रिम्स प्रबंधन और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। वहीं अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। कई जगहों पर स्थाई स्ट्रक्चर को गिराया भी गया। हालांकि कार्रवाई के दौरान आसपास में रहने वाले लोग मैदान में सुबह से शाम तक जमे रहे। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस बल को तैनात किया गया है। बरियातू थाना के पीछे बने झोपड़ी और गुमटियों को हटाया गया है। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का आरोप है कि उन्हें अपना ढांचा हटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। विरोध के बावजूद टीम बिना रुके अतिक्रमण हटाने में जुटी रही। प्रशासन की ओर से बताया गया कि लोगों के घरों और संरचनाओं पर नोटिस चिपकाया गया था। इसके बावजूद लोगों ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया।

डीआईजी ग्राउंड में अपार्टमेंट की गिराई गई अवैध बाउंड्री

रिम्स कैंपस में तोड़े गए ढांचे

समान कार्रवाई की उठी आवाज

विरोध कर रहे लोगों ने टीम पर आरोप लगाया कि वे बड़े लोगों के निर्माण पर कार्रवाई नहीं कर रहे है। जबकि उनका निर्माण भी अवैध है। अगर कार्रवाई हो रही है तो सभी पर समान रूप से होना चाहिए। इस ठंड में लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। कंपाने वाली ठंड में हमलोग कहां जाएंगे। इसके अलावा लोगों ने कहा कि हटाने से पहले रहने की व्यवस्था भी प्रशासन को करनी चाहिए। वहीं जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि अगले दस दिनों में रिम्स की पूरी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कर लिया जाएगा।

तत्काल व्यवस्था बदलने की मांग

पुजारी के मंदिर परिसर में नहीं रहने से सुरक्षा भी प्रभावित हुई है। बरियातू क्षेत्र के महावीर मंडल के अध्यक्ष राजकिशोर, प्रकाश चंद्र सिन्हा और नवेंदु उपाध्याय ने रिम्स प्रशासन से तत्काल व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुजारी के आवास हटने के बाद से बरियातू शिव मंदिर, रिम्स स्टाफ क्वार्टर मंदिर, मिलन चौक हनुमान मंदिर समेत रिम्स परिसर के अन्य मंदिरों में भगवान को निर्धारित समय पर भोग नहीं लग पा रहा है और न ही आरती की जा रही है।

मंदिरों की सुरक्षा पर पड़ रहा प्रभाव

रिम्स परिसर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान ने तूल पकड़ लिया है। वहीं इसका असर अब कैंपस स्थित मंदिरों की सुरक्षा पर दिख रहा है। लोगों का कहना है कि अवैध अतिक्रमण हटाने को समर्थन है। लेकिन जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मंदिर की सुरक्षा पर भी रिम्स प्रबंधन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। अतिक्रमण हटाने के क्रम में मंदिरों के पुजारी के आवास को भी हटा दिया गया, जिसके बाद से मंदिरों में नियमित पूजा-पाठ, भोग और सुबह-शाम की आरती बाधित हो गई है। महावीर मंडल के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में किसी भी मंदिर में कोई घटना या क्षति होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी रिम्स प्रशासन की होगी। उन्होंने मांग की है कि मंदिरों में पुजारी के रहने, पूजा-पाठ की नियमित व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जिससे कि धार्मिक गतिविधियां पूर्व की तरह सुचारू रूप से चल सकें।

झारखंड शराब घोटाला : ईडी ने आरोपियों से जेल में की पूछताछ

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों से ईडी ने पूछताछ की। ईडी की एक टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार पहुंची, जहां उसने एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों महेश सीताराम, परेश ठाकोर, विक्रम ठाकोर, बिपिन जाधवभाई परमार और जगन ठाकोर देसाई से पूछताछ की। ईडी ने इससे पहले पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन देकर इन आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। अदालत की मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी ने जेल परिसर में ही पूछताछ की कार्रवाई पूरी की। सभी आरोपी एसीबी द्वारा कांड संख्या 9/25 के तहत गिरफ्तार किए गए थे और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी ने अदालत में दिए आवेदन में कहा था कि एसीबी की प्रारंभिक जांच (पीए-3/2024) में यह सामने आया कि मेसर्स विजन हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने फर्जी बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर शराब का कारोबार किया और सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच में पता चला कि विजन हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 5.35 करोड़ रुपये और मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 5.02 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी। आरोपियों में महेश सीताराम विजन हॉस्पिटैलिटी एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं, जबकि परेश ठाकोर, विक्रम ठाकोर और बिपिन जाधवभाई परमार कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हैं। वहीं,मार्शन इनोवेटिव सिक्यूरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक जगन ठाकोर देसाई हैं। गौरतलब है कि एसीबी ने मई माह में घोटाले की प्रारंभिक जांच पूरी करने के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी।

कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और मंत्री इरफान अंसारी भिड़े, स्पीकर को देना पड़ा नियमन

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन उस समय नाटकीय हो गया, जब सत्ताधारी महागठबंधन के दो प्रमुख चेहरे, कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव और कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों के इलाज को लेकर एक-दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करने लगे। ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान शुरू हुई बहस इतनी गरमा गई कि स्पीकर रबींद्र नाथ महतो को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़ा और अंत में दोनों नेताओं को चैंबर में बैठकर बात करने की सलाह देनी पड़ी। प्रदीप यादव ने सबसे पहले आंकड़े पेश किए। कहा - राज्य में करीब 11 हजार बच्चे इन तीनों गंभीर रक्त विकारों से पीड़ित हैं। इन्हें हर महीने एक से दो बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए। लेकिन, न तो राज्य में ब्लड सेपरेशन यूनिट की पर्याप्त व्यवस्था है, न ही निःशुल्क इलाज की ठोस नीति। परिजन रांची से रायपुर, रायपुर से दिल्ली भटकते रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लड़कों को 15 लाख और लड़कियों को 18 लाख देती है। कर्नाटक 20 लाख, बिहार-ओडिशा 15 लाख तक देते हैं। प्रदीप यादव ने चार सवाल दागे, मरीजों का सही सर्वे है। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था क्या है। ब्लड डोनर को चिन्हित करने का कोई प्लान है। केंद्र से मिलने वाली 10 लाख रुपये की मदद का क्या हुआ। जवाब देने के लिए जैसे ही इरफान अंसारी खड़े हुए, उन्होंने पहले पुराना हिसाब चुकता किया। कल माननीय सदस्य ने हंसडीहा अस्पताल में 25 करोड़ के उपकरण चोरी का मामला उठाया था।

छात्र अधिकार पदयात्रा विधानसभा पहुंचने से पहले रोकी गई, हंगामा

RANCHI : जेएलकेएम के नेतृत्व में निकाली गई छात्र अधिकार पदयात्रा में मंगलवार को उस समय हंगामा मच गया, जब विधानसभा परिसर से पहले ही पुलिस प्रशासन ने इसे रोक दिया। यह पदयात्रा पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा और संगठन के कार्यकर्ता शामिल थे। पदयात्रा जैसे-जैसे विधानसभा की ओर बढ़ रही थी, प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन विधानसभा से पहले ही सुरक्षा बलों ने बैरिकेड लगाकर यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और मौके पर जमकर हंगामा किया।

निगम का अभियान फेल, रोड किनारे फिर से सज गईं दुकानें

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम ने राज्य स्थापना दिवस से पूर्व पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। इस दौरान राजधानी की प्रमुख सड़कों से युद्धस्तर पर अतिक्रमण हटाया। वहीं दुकानें जब्त भी की गई थीं। लेकिन, कुछ दिनों के बाद ही व्यवस्था बेपटरी हो गई है। रोड किनारे फिर से वेंडरों ने कब्जा जमा लिया है। फुटपाथ पर उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। इस वजह से पैदल चलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं हर समय उन्हें गाड़ियों से धक्का लगने का डर सताता रहता है।

रोड साइड दुकान लगाने वाले वेंडरों को हटाकर नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने बड़े-बड़े बोलार्ड लगाए थे। जिससे कि वहां पर दोबारा दुकानें न लगाई जा सके।

लेकिन, वेंडरों का मन इतना बढ़ चुका है कि उनलोगों ने बोलार्ड को हटा दिया। इसके बाद वहीं पर दुकान लगाकर कारोबार कर रहे है। इसके बावजूद नगर निगम इन वेंडरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिससे साफ है कि निगम की इंफोर्समेंट टीम अतिक्रमण हटाने के नाम पर केवल आई वाश करती है।

छात्रवृत्ति पर केंद्र से गुहार लगाने दिल्ली जाएगी राज्य सरकार

RANCHI : लंबित छात्रवृत्ति को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ इसको लेकर सियासत तेज है, वहीं दूसरी ओर राज्य के लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर, विपक्ष के सवालों से घिरा कल्याण विभाग की स्थिति सांप-छछूंदर वाली हो गई है। काफी जद्दोजहद के बाद इस साल जो प्री मैट्रिक के ओबीसी छात्रों के लिए केंद्रीय मद से 4 करोड़ मिला है, वह राशि भी केंद्र को वापस होनेवाली है और राज्य सरकार को नए सिरे से समय-समय पर छात्रवृत्ति की राशि की मांग केंद्र से करनी होगी। तकनीकी प्रावधान के तहत केंद्रीय मद की राशि जब तक राज्य को नहीं मिलेगी, तब तक वित्त विभाग राज्य मद से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर सकता है।

नई पहल नगर निगम प्रशासक ने की मीटिंग, कहा- बस स्टैंड और बाजारों का होगा विकास

अवैध कॉमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरह लगाई जाएगी रोक

PHOTON NEWS RANCHI : मंगलवार को रांची नगर निगम में प्रशासक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें शहर के राजस्व सृजन, अवैध कॉमर्शियल एक्टिविटी पर रोक, बस स्टैंडों और बाजार परिसंपत्तियों के विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बाजार शाखा द्वारा राजस्व कलेक्शन से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिया गया कि नगर क्षेत्र में लगे सभी होर्डिंग्स और मोनोपोल्स का भौतिक निरीक्षण, नंबरिंग और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। निरीक्षण रिकार्ड में प्रत्येक साइट का सटीक स्थान, परमिशन साइज, स्वीकृत अवधि, आवंटी या एजेंसी का नाम और बकाया राशि का विवरण अपडेट करे। वहीं अनधिकृत और नियमों के विरुद्ध स्थापित संरचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया।

बकाएदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई : नगर निगम ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन एजेंसियों और बाजार परिसरों के बकायेदारों द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। निर्देश दिया गया कि नियत अवधि में भुगतान न होने पर संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और परिसंपत्तियों का पुनः आवंटन किया जाएगा। विशेष रूप से नागाबाबा खटलाल और अटल स्मृति वेंडर मार्केट में लंबित किराया वसूली और किरायेदारी पुनर्मूल्यांकन अभियान शुरू करने की तैयारी है।

आवासीय क्षेत्रों में व्यापार करने वालों को नोटिस : बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित कॉमर्शियल एक्टिविटी के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर उनका ट्रेड लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

डिजिटल रिकॉर्ड रखने पर जोर

नगर निगम ने अपने स्वामित्व वाली सभी राजस्व सृजन करने वाली परिसंपत्तियों जैसे होर्डिंग साइट्स, बाजार परिसरों की दुकानें, बस स्टैंड परिसर, पार्किंग स्थल और वाणिज्यिक इकाइयों का व्यवस्थित नंबरिंग और डिजिटल रिकार्ड करने का निर्णय लिया। इससे परिसंपत्ति प्रबंधन और राजस्व निगरानी अधिक प्रभावी होगी।

तैयार किए जाएंगे डीपीआर व प्रजेंटेशन

नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर के बस स्टैंडों और बाजार परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण व यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए संबंधित एजेंसियों और तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर विस्तृत डीपीआर व प्रजेंटेशन तैयार किए जाएंगे। निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान और बेस प्राइस तय करने के लिए एक विशेष समिति गठित करने पर सहमति बनी, ताकि भविष्य की निविदा प्रक्रिया और संपत्ति बंदोबस्ती पारदर्शी ढंग से संचालित हो सके।

हटिया रेलवे स्टेशन से 23 किलो गांजा बरामद

RANCHI : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) हटिया और फ्लाइंग टीम रांची ने संयुक्त अभियान चलाकर नशा तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम किया है। आरपीएफ रांची के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर हटिया रेलवे स्टेशन पर की गई इस कार्रवाई में कुल 23 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इसकी बाजार कीमत करीब 11,50,000 रुपये है। जानकारी के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह और फ्लाइंग टीम के सदस्यों ने प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध रूप से बैठे दो व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी। बैग से प्लास्टिक पैकिंग में रखा बड़ा गांजा बरामद हुआ। मौके पर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त अशोक कुमार सिंह की मौजूदगी में चारों पैकेटों की डीडी किट से जांच की गई, जो पॉजिटिव पाई गई।

छह वर्षों में एक भी स्थानीय नियोजन नीति नहीं ला सके हेमंत सोरेन : प्रतुल

PHOTON NEWS RANCHI : भाजपा ने सरकार को एक बार फिर से घेरा है। सरकार पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का वादा कर हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया है। यह सरकार वास्तविक में ठगुआ सरकार है। झारखंड की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि छह वर्ष में हेमंत सोरेन सरकार एक भी स्थानीय नियोजन नीति क्यों नहीं ला सकी। आज तक न कटऑफ डेट घोषित हुई, न खतियान आधारित नीति बनी, न युवाओं को कोई ठोस रास्ता मिला। यह सरकार केवल आश्वासन देती है और फिर उसपर मौन साध लेती है।

उन्होंने कहा कि यह वहीं हेमंत सोरेन हैं जिन्होंने 1932 के खतियान आधारित नीति के मुद्दे पर 2012 में अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस लेकर बड़ा नाटक किया था। तब यह उनके लिए असली जनभावना थी। लेकिन आज छह वर्षों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बावजूद नीति के नाम पर शून्य उपलब्धि इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। सच यह है कि हेमंत सरकार की मंशा नहीं, सिर्फ माला जपने वाली मुनादी है।

समाचार सार

डीआरएम ने दो ट्रैकमैन को किया सम्मानित

CHAKRADHARPUR : दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-मुंबई रेलमार्ग पर गत शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया था। राजखरसावां-महालीमोरूप रेलखंड पर देर रात गश्त के दौरान ट्रैकमैन बनबिहारी महतो और हरियल हेम्ब्रम ने डाउन लाइन में वेल्ड फेल्योर (जोड़ में टूट) का पता लगाया और एक मालगाड़ी को समय रहते रोक दिया। उनकी तत्परता से एक बड़ा रेल हादसा टल गया। डीआरएम तरुण हुरिया ने मंगलवार को दोनों ट्रैकमैन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

गणतंत्र दिवस परेड में जाएगा एसडीयू का छात्र

GHATSILA : सोना देवी विश्वविद्यालय का छात्र देवऋषि कश्यप नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा। उसका चयन नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी के आरडीसी कैंप में हो गया है। देवऋषि बीटेक थर्ड सेमेस्टर के छात्र है। देवऋषि कश्यप को पिछले दिनों जमशेदपुर में 721 कैडेटों में सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुना गया था। नई दिल्ली के एनसीसी शिविर में भी देवऋषि को सर्वश्रेष्ठ ड्रिल के लिए पुरस्कृत किया गया।

सोना देवी विवि में वार्षिक खेल उत्सव शुरू

GHATSILA : सोना देवी विश्वविद्यालय में मंगलवार से चार दिवसीय वार्षिक खेल उत्सव- इग्नाइट 2025 शुरू हुआ। मुख्य अतिथि व कुलपति डॉ. ब्रजमोहन पाटपिंगुआ ने उद्घाटन सत्र में छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय की खेल संस्कृति को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। ऐसे आयोजनों से न केवल खेल प्रतिभा निखरती है, बल्कि चरित्र निर्माण भी होता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के खेल विकास मॉडल की प्रशंसा करते हुए सभी प्रतिभागियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामना दी। कुलसचिव गुलाब सिंह आजाद ने कहा कि विश्वविद्यालय सदैव छात्रों को सशक्त बनाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहता है।

बूथ स्तर पर कांग्रेस को बनाएं मजबूत : कमलेश

CHAIBASA : कांग्रेस भवन चाईबासा और चक्रधरपुर वन विश्रामागार में मंगलवार को ग्राम पंचायत व वार्ड स्तरीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत प्रखंड तथा नगर कमेटी का गठन हो चुका है। मंडल अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। अब जिला अध्यक्ष उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर की कमेटी बनाई जाएगी। इसमें बूथ स्तर पर एक बीएलए भी होगा। बीएलए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। पंचायत कमेटी हर माह बैठक करेगी, जिसमें मंडल अध्यक्ष अवश्य भाग लेंगे। जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पर्यवेक्षक- सह- पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार बलमुचू, सूर्यकांत शुक्ला, अमूल्य नीरज खलखो आदि भी शामिल थे।

इंटर रेलवे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप शुरू

CHAKRADHARPUR : चक्रधरपुर मंडल स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 39वें ऑल इंडिया इंटर रेलवे बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन मंगलवार को डीआरएम तरुण हुरिया ने किया। 8 से 10 दिसंबर तक महात्मा गांधी सभागार में हो रही प्रतियोगिता में देशभर से आए 85 बॉडी बिल्डर और 141 अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के पहले चरण में 55 किलोग्राम भार वर्ग में बॉडी बिल्डरों ने दमखम दिखाया। इस अवसर पर सीनियर डीएमई राजीव रंजन रसिक, खेल अधिकारी हेमंत मधुर, डीएफएम को-ऑर्डिनेशन विनय कुमार शर्मा और सेरसा के सचिव तेज नारायण प्रसाद भी मौजूद थे। डीआरएम ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रतियोगिता रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अच्छा अवसर है, जहां वे शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं।

एनआईटी जमशेदपुर में 13 प्रोफेसरों की वैकेंसी

JAMSHEDPUR : राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जमशेदपुर में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 13 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए संस्थान ने आधिकारिक वेबसाइट www.nitjsr.ac.in पर विज्ञापन प्रसारित किया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 31 दिसंबर तक http://www.nitjsr.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है। यह भर्ती भारत गजट अधिसूचना अधिनियम-2019, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रावधानों के तहत होगी। कोटिवार निकाली गई रिक्ति में सामान्य : 04, ईडब्ल्यूएस : 01, एसटी : 04, एससी : 02 और ओबीसी : 02 हैं।

जांच में खुलासा, नेपाल में मानव तस्करों की गिरफ्त में हैं 27 बच्चे

पहले सामने आई थी 11 बच्चों के बंधक होने की बात, प्रशासन की जांच टीम पहुंची गांव

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के 27 बच्चे मानव तस्करों के जाल में फंस गए हैं। बच्चों को नेपाल के काठमांडू में बंधक बनाए जाने की जानकारी देते हुए उनके परिजनों ने उपायुक्त चंदन कुमार से गुहार लगाई है। परिजनों की शिकायत के बाद नेपाल में फंसे नाबालिग बच्चों के मामले पर डीसी चंदन कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो को मामले की जांच का आदेश दिया है। एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, एसडीपीओ बहामन टुटी और मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार के साथ एक टीम मंगलवार को मामले की जांच के लिए बच्चों के गांव पहुंची। अधिकारियों ने चाईबासा के सदर प्रखंड स्थित पंडावीर पंचायत के रंगामाटी गांव पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू की। इससे पहले तबलीगो गांव के 11 बच्चों को नेपाल ले जाने की बात सामने आई थी, जबकि अब जगन्नाथपुर और सोनुवा प्रखंड से भी बच्चों को ले जाने की बात सामने आ रही है। कुल 27 बच्चों को नेपाल की राजधानी काठमांडू ले जाया गया है। परिजनों ने बताया कि वहां सभी बच्चों का सिर मुंडवा दिया गया। इससे उन्हें बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने की आशंका हो रही है। यह बात नेपाल से भागकर आए दो बच्चों ने बताई है। इसके बाद गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक हड़कंप मच गया है।

परिजनों से मामले की जानकारी लेते एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो ● फोटोन न्यूज

झारखंड पुलिस ने 257 का किया था रेस्क्यू

गौरतलब है कि झारखंड में मानव तस्करी की समस्या गंभीर है। वर्ष 2023-24 में राज्य में कुल 78 मानव तस्करी के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 282 लोग शिकार हुए। झारखंड पुलिस ने इन मामलों में 257 लोगों का रेस्क्यू किया था, जिसमें 173 युवक और 84 युवतियां एवं महिलाएं शामिल थीं।

खाना बनाने को लेकर पत्नी से उलझा शराबी गला घोंटकर मार डाला

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना क्षेत्र में हत्या का एक मामला सामने आया है। यहां संजय शर्मा नामक व्यक्ति ने खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद अपनी पत्नी निशा शर्मा को गला घोंटकर मार डाला। पत्नी की हत्या करने के बाद वह व्यक्ति उसका शव उठा कर दूर ले गया और झाड़ी में फेंक दिया। बाद में ग्रामीणों ने शव देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि संजय शर्मा नशे का आदी था। वह आए दिन शराब पीता था। वह शराब पीकर घर आया था। तभी उसने पत्नी से खाना बनाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट की आ गई। संजय शर्मा ने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

अवैध कोडीन कफ सिरप के साथ किशोर सहित दो गिरफ्तार

JAMSHEDPUR : मानगो के आजादनगर थाना अंतर्गत पुलिस ने अवैध कोडीन कफ सिरप की 27 बोतल के साथ किशोर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष छापामारी दल ने गिरफ्तार युवक को मंगलवार को जेल भेज दिया। पुलिस टीम को सोमवार को गुप्त सूचना मिली कि आजादनगर थाना क्षेत्र के मुर्दा मैदान के पास दो व्यक्ति मादक पदार्थ बेचने पहुंचे हैं। इसके बाद डीएसपी पटमदा के नेतृत्व में छापेमारी दल पहुंचा और बताए गए हुलिए के आधार पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। इसमें एक आरोपी इमरान खान उर्फ विक्की है, जो आजादनगर के चेपापुल का रहने वाला है। दूसरा पकड़ा गया आरोपी किशोर है। दोनों के पास से प्रतिबंधित विंसेरेक्स कफ सिरप बरामद की गई है। नाबालिग को निरुद्ध किया गया है।

वेदांता को मिलेगी केबुल कंपनी पूर्व कर्मचारियों ने किया विरोध

PHOTON NEWS JSR : एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) की कोलकाता बेंच में जमशेदपुर की केबुल कंपनी को लेकर हुए फैसले के खिलाफ मजदूरों ने आवाज बुलंद की है। केबुल कंपनी के मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाली केबुल संघर्ष समिति ने मंगलवार को मीटिंग कर फैसला लिया कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलटी दिल्ली में चैलेंज किया जाएगा। समिति के महामंत्री यूके शर्मा ने कहा कि केबुल कंपनी, वेदांता कंपनी को देने का फैसला हुआ है। लेकिन, मजदूरों के हित को लेकर कई बिंदुओं पर इस फैसले में कोई चर्चा नहीं की गई। उनका कहना है कि इस फैसले से मजदूर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि 1100 के करीब रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जिनका पीएफ, ईसीआई और बकाया वेतन की रकम मिलनी चाहिए। इसके अलावा 500 ऑन रोल कर्मचारी हैं जिनका फैसले में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनकी नौकरी बरकरार रहनी चाहिए। यूके शर्मा ने कहा कि 31 मार्च साल 2000 तक कंपनी में 4 करोड़ 53 लाख 66 हजार 69 रुपये का तैयार माल था। इसमें से एक करोड़ 95 लाख 5357 रुपये का माल बेचा गया था। शेष 3 करोड़ 24 लाख 10712 रुपये का माल कहां गया। उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 1999 तक केबुल कंपनी ने 16 करोड़ 69 लाख 54 हजार एक रुपये की परिसंपत्ति खरीदी थी। 31 दिसंबर साल 2000 तक 264 लोग इस कंपनी से रिटायर हुए थे। उस अवधि में इनकी 2 करोड़ 70 लाख 41 हजार 95 रुपये की ग्रेच्युटी की राशि बकाया है। इस राशि में से मात्र 65 हजार रुपये का ही भुगतान हुआ था।

बैठक करते यूनियन के सदस्य ● फोटोन न्यूज

सीआरपीएफ जवान की परेड के दौरान हुई मौत, गोरखपुर भेजा गया पार्थिव शरीर

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में सीआरपीएफ-197 बटालियन के जवान गोपालजी सिंह (46) की मंगलवार को परेड के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि हृदयगति रुकने से वे गिर पड़े, जिससे वहां अफरातफरी मच गई। परेड में शामिल बटालियन के जवान उन्हें आनन-फानन सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवानों ने बताया कि सुबह कैंप में सभी जवान परेड कर रहे थे, तभी अचानक गोपालजी की तबीयत बिगड़ गई। उनके शव को पैतृक गांव गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के बेलघाट के सिसवा बाबू गांव भेजा जा रहा है। जवानों ने बताया कि गोपालजी सिंह कुछ दिनों से छुट्टी पर थे। वह अपने बेटे को आईटीबीपी (इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस), दिल्ली में सब-इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन कराकर रविवार को ही चाईबासा लौटे थे। सोमवार से उन्होंने ड्यूटी शुरू की थी कि ऐसा हो गया। उनकी मौत से सीआरपीएफ कैंप में सन्नाटा पसर गया है।

सेल की गुवा माइंस में बाहरी लोगों की बहाली पर यूनियनों का प्रदर्शन

जेनरल ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन करते यूनियन के लोग ● फोटोन न्यूज

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा स्थित सेल की माइंस में कथित रूप से 20 बाहरी व्यक्तियों की बहाली की गई है। इसके विरोध में मंगलवार को संयुक्त यूनियनों ने जेनरल ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। नारेबाजी और विरोध के बीच यूनियनों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सेल प्रबंधन बाहरी लोगों की बहाली को तुरंत प्रभाव से नहीं रोकता है, तो उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। मजदूर नेता रामा पांडे ने कहा कि जब तक 20 बाहरी लोगों की बहाली पर रोक नहीं लगती, तब तक डिस्पैच भी बंद रहेगा। पांडे ने कहा कि डेढ़ साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व पूर्व सांसद गीता कोड़ा के साथ बोकारो-सेल के पदाधिकारी व यूनियन नेताओं में लिखित एग्रीमेंट हुआ था। इसमें कहा गया था कि स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाएगी। यहां स्थानीय को नहीं देकर बाहरी लोगों को नौकरी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि सेल की किरीबुरु माइंस में बाहरी मजदूरों को ज्वाइन कराकर गुवा में पोस्टिंग की गई है।

पशु व्यापारी से बदमाशों ने लूटे 85 हजार रुपये

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी ओपी थाना अंतर्गत बलांडिया जंगल के पास लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। हाटगम्हरिया के साप्ताहिक हाट (बाजार) से लौट रहे एक पशु व्यापारी से अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 85 हजार रुपये लूट लिए। सोमवार शाम को हुई इस घटना को पहले से घात लगाए अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया। व्यापारी से रुपये लूटने के बाद बदमाश फरार हो गए। जानकारी के अनुसार, कुमारडुंगी निवासी अर्जुन महाकुड़ ने हाटगम्हरिया के साप्ताहिक बाजार में दो जोड़ा बैल बेचा था। इससे उसे 85 हजार रुपये मिले थे। अर्जुन महाकुड़ रुपये लेकर घर लौट रहे थे। तभी बलांडिया जंगल में दो अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल दिखाते हुए रोका। फिर डराने के लिए फायरिंग भी की। इसके बाद चाकू दिखाते हुए जंगल की ओर ले गए। वहां पहले से घात लगाए छह बदमाश आ गए, फिर व्यापारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। धारदार हथियार से हमला कर उनसे रुपये लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद कुमारडुंगी थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यहां बता दें कि सोमवार शाम को ही चक्रधरपुर के युवक से भी चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लूट की घटना हुई थी। वह युवक जमशेदपुर से चक्रधरपुर लौट रहा था। कार सवार अपराधियों ने उसकी बाइक को ओवरटेक करके करीब 11 हजार रुपये लूट लिए थे।

छात्रों ने रैली निकालकर मांगा छात्रवृत्ति भुगतान

JAMSHEDPUR : छात्रवृत्ति के लिए मंगलवार को छात्रों ने साकची के आमबगान मैदान से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम डीसी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर छात्रों को फौरन छात्रवृत्ति देने की मांग उठाई गई है। गौरतलब है कि भाजपा ने छात्रवृत्ति के मुद्दे पर ही सोमवार को विधानसभा में हंगामा किया था। इसके बाद यह रैली निकाली गई। यह रैली किसी छात्र संगठन के बैनर तले नहीं निकली। छात्रों का कहना है कि इसमें विभिन्न स्कूलों-कॉलेजों के छात्र शामिल थे। राज्य में ई- कल्याण छात्रवृत्ति में पिछले दो सालों से कथित तौर पर हो रही देरी को लेकर छात्र-छात्राओं में नाराजगी है। आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र मुख्य रूप से इसी मदद पर निर्भर रहते हैं। मगर, छात्रवृत्ति न मिलने के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो रहे हैं।

तीन प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस, सिर धुनती रहीं छात्राएं, एक घंटे बाद यूनिवर्सिटी पहुंचीं कंट्रोलर

PHOTON NEWS JSR : जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी में स्नातक थर्ड समेस्टर की परीक्षा चल रही है। मंगलवार को एक ही प्रश्नपत्र में तीन प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिए गए, जिसे लेकर छात्राएं सिर धुनती रहीं। एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्नपत्र मिलते ही छात्राओं ने तीन प्रश्नों पर आपत्ति जताई। उन्होंने वीक्षकों को इस बात की जानकारी दी, लेकिन वीक्षक ने बताया कि परीक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन की अनुमति बिना कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में छात्राएं परेशान रहीं। छात्राओं ने संकाय की डीन डॉ. दीपा शरण से भी लिखित शिकायत की है। छात्राओं ने बताया कि परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद परीक्षा नियंत्रक यूनिवर्सिटी पहुंचीं। प्रश्नपत्र की जानकारी लेने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया, तब छात्राओं ने थोड़ी राहत की सांस ली। यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रक डॉ. रमा सुब्रह्मण्यम ने कहा कि प्रश्नपत्र का पैकेट खुलने से पहले उन्हें भी प्रश्नों की जानकारी नहीं होती है। जो भी हो, तीन प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्न भी तो थे। छात्राएं उन प्रश्नों को भी अटेंप्ट कर सकती थीं। वैसे इस पर विचार किया जाएगा। इसे लेकर छात्राओं को भी आश्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि इससे पूर्व परीक्षा के पहले दिन दो दिसंबर को भी निगमीय वाणिज्य की परीक्षा में छात्राओं ने एक प्रश्न पर आपत्ति जताई थी।

यूनिवर्सिटी कैंपस में जमा छात्राएं ● फोटोन न्यूज

इस संबंध में संकाय की डीन को आवेदन देकर एक प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होने की शिकायत की गई थी। बताया जाता है कि अभी तक पहली शिकायत का कोई हल नहीं निकला।

विसंगति कक्षा एक से 10 तक के लिए आए हैं 1,33,931 आवेदन, जल्द खाते में जाएगी रकम

प्री-मैट्रिक के लिए मिले 20 करोड़, पोस्ट-मैट्रिक में 'ठन-ठन गोपाल'

● इंटर व उच्च शिक्षण संस्थानों के स्टूडेंट्स के लिए अब तक नहीं मिला फंड

MUJTABA RIZVI @ JSR : झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (2025-26) के वितरण के लिए 20 करोड़ रुपये का फंड दे दिया है। यह रकम जिले के कल्याण विभाग के खाते में आ गई है। इस रकम से जिले में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जबकि, कक्षा आठ से कक्षा 10 के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति का फंड जल्द आने वाला है। बताया जा रहा है कि छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की तरफ से आवेदन करने का सिलसिला चल रहा है। जल्द ही जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी और इसके बाद आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के बाद कक्षा एक से आठ तक के सभी स्टूडेंट्स के खाते में छात्रवृत्ति की रकम भेज दी जाएगी। गौरतलब है कि छात्रवृत्ति में देरी के आरोप में इन दिनों विधानसभा में हंगामा हो रहा है। जमशेदपुर में भी छात्रों के एक समूह ने रैली निकाल कर डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया है। ऐसे में द फोटोन न्यूज ने अपने जिले में छात्रवृत्ति की स्थिति खंगाली तो पता चला कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के हालात तो ठीक हैं। मगर, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर फंड की दिक्कत आ रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पोस्ट मैट्रिक के लिए 31 तक करें आवेदन

जिला कल्याण विभाग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के नाम पर कक्षा एक से कक्षा 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देता है। कक्षा एक से कक्षा आठ तक के विद्यार्थियों को 2250 रुपये जबकि, कक्षा नौ और 10 के स्टूडेंट्स को 4500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (2025-26) के लिए अब तक एक लाख 33 हजार 931 आवेदन आ चुके हैं। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन सबमिट करने का सिलसिला चल रहा है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए फंड का इंतजार

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिला कल्याण विभाग फंड का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इस मद के लिए फंड देती है। मगर, केंद्र से अब तक राज्य को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के मद में फंड नहीं मिल पाने की वजह से देर हो रही है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा किए जा रहे हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष के 12 हजार से अधिक स्टूडेंट्स महरूम

पिछले वित्तीय साल से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में दिक्कत शुरू हुई है। पिछले वित्तीय साल में 22 हजार 725 स्टूडेंट्स को वजीफा दिया गया। मगर, फंड की कमी की वजह से 12 हजार 141 स्टूडेंट्स छात्रवृत्ति से वंचित रह गए। यह छात्र अब भी वजीफे के लिए जिला कल्याण विभाग का चक्कर काट रहे हैं। इसी तरह, वित्तीय साल 2023-24 में 23 हजार 64 छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। इस वित्तीय साल के भी 464 छात्र छात्रवृत्ति के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं।

पिछले साल वंचित रह गए थे 6373 स्टूडेंट्स : प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (2024-25) के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से एक लाख 43 हजार 348 स्टूडेंट्स को वजीफा दिया गया था। 6373 छात्र छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे। इन्हें इस साल के फंड से छात्रवृत्ति देने की कवायद चल रही है। इसके लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है।

जेएलएन कॉलेज की जमीन पर हो रहा कब्जा, प्राचार्य ने लगाई गुहार

पुराना बस्ती स्थित कॉलेज की चारदीवारी के पास अतिक्रमण का जायजा लेते प्राचार्य व अन्य

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की जमीन का अतिक्रमण कर दबंगों द्वारा वहां निर्माण कराया जा रहा है। कॉलेज के मुख्य द्वार की दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में ढांचा निर्माण के लिए खोदाई भी कर दी गई है। मंगलवार को जब इसकी जानकारी प्राचार्य एवं कॉलेज प्रबंधन को मिली तो सब चौंक गए। इसके बाद कॉलेजके प्राचार्य डॉ. श्रीनिवास कुमार, प्राध्यापक डॉ. अरुण कुमार, प्रो. मनसा महतो और प्रधान लिपिक पंकज प्रधान अतिक्रमित स्थल देखने गए। कॉलेज की विशाल चारदीवारी से सटे झाड़ियों से घिरे दक्षिणी हिस्से का अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां दूर से सिर्फ झाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन पास जाने पर दिखता है कि नींव के लिए मिट्टी खोदी गई है। मार्केट कांप्लेक्स के निर्माण की भांति सात कमरों के लिए चूने से घेरा भी बनाया गया है। इसके बाद प्राचार्य ने एसडीओ और अंचल अधिकारी से कॉलेज की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई है। प्राचार्य ने बताया कि दो वर्ष पूर्व भी इन दोनों अधिकारियों को पत्र लिखकर कालेज की अतिक्रमित की जा रही भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई थी, लेकिन कोई पहल नहीं हुई।

मनोविज्ञान की फील्ड में बना सकते हैं करियर

मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें प्रत्येक आयुवर्ग के लोग विशेषज्ञता हासिल कर अपना करियर बना सकते हैं। इसमें मानव मन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मसलन, मस्तिष्क तनाव में कैसे काम करता है, यह कैसे भाषा सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है। इस सेक्टर में विशेषज्ञता और रुचियों के आधार पर मनोविज्ञान डिग्री धारकों के लिए कई अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हैं, जो कि इस प्रकार हैं-

- मनोविज्ञानी
- मनोचिकित्सक
- समाज सेवक
- काउंसलर
- शैक्षिक मनोवैज्ञानिक
- मानव संसाधन प्रबंधक
- अध्यापक
- अनुसंधान भूमिकाएं
- मीडिया भूमिकाएं
- मनोविज्ञान में करियर

मनोविज्ञान का कोर्स करने के बाद छात्र पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ स्पोर्ट्स, सोशल वर्क, थेरेपी एंड काउंसलिंग जैसे कई सेक्टर में करियर बना सकते हैं। यहां पर वे सलाहकार, अनुसंधान-आधारित, उपचार-आधारित या चिकित्सीय की भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मीडिया और अन्य रचनात्मक फील्ड में नौकरियों सहित मनोविज्ञान स्नातकों के लिए कई ऑप्शन भी हैं।

चार्टर्ड मनोवैज्ञानिक

एक चार्टर्ड मनोवैज्ञानिक के तौर पर आप व्यावसायिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, खेल और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। यहां आप सभी पृष्ठभूमि के लोगों, रोगियों और क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप कुछ मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर बेहतर ढंग से समझने और सलाह देने के लिए आप व्यवहार, विचारों और भावनाओं का विश्लेषण कर सकते हैं। हालांकि यदि आप मनोचिकित्सक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेडिकल डिग्री हासिल करने की आवश्यकता होगी।

मनोचिकित्सक

एक मनोचिकित्सक के तौर आपको व्यक्तियों, जोड़ों, समूहों या परिवारों के साथ काम करता होगा। जिससे आप अपने क्लाइंट्स को भावनात्मक और रिश्ते से संबंधित मुद्दों, तनाव और यहां तक कि व्यसन सहित मनोवैज्ञानिक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सके। इनमें संज्ञानात्मक व्यवहार विधियां, मनोविश्लेषणात्मक और मनोगतिक चिकित्सा, साथ ही कला चिकित्सा, नाटक चिकित्सा, ह्यूमनिस्टिक और एकीकृत मनोचिकित्सा, सम्मोहन-मनोचिकित्सा और अनुभवात्मक चिकित्सा शामिल हैं।

समाज सेवक

एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपको ऐसे लोगों की स्थितियों में सुधार लाने के लिए काम करना होगा, जो अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं जैसे बच्चों या बुजुर्गों का या ऐसा ही अन्य कोई ग्रुप, विकलांग लोगों और अपराध और दुर्व्यवहार के शिकार लोगों सहित अन्य कई।
सामाजिक कार्यकर्ता स्कूलों, घरों, अस्पतालों या अन्य सार्वजनिक एजेंसियों के भीतर काम कर सकते हैं।

काउंसलर

एक काउंसलर लोगों को उनके जीवन, भावनाओं और अनुभवों के साथ बेहतर तरीके से सामंजस्य बिठाने में मदद करता है। यहां पर क्लाइंट की बातों को ध्यान से सुनना एक काउंसलर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक काउंसलर में सुनने, सहानुभूति देने, सम्मान और धैर्य प्रदान करने की क्षमता साथ विश्लेषण करने की क्षमता होनी जरूरी है, ताकि क्लाइंट को उनकी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटने में सक्षम बनाया जा सके। एक काउंसलर अक्सर विवाह और परिवार, स्वास्थ्य, दुर्व्यवहार, पुनर्वास, शिक्षा, दुख, मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन और बाल रोग सहित अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

शिक्षा में मनोविज्ञान करियर

मनोविज्ञान कोर्स के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यहां आप शिक्षा के साथ-साथ शैक्षिक चिकित्सा, शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा के भीतर सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान स्नातक प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में काम कर रहे शिक्षकों के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जेल के अंदर के युवा अपराधियों को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। वहीं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में करियर में प्रवेश करने के लिए आपको मास्टर / पीएचडी योग्यता की आवश्यकता होगी। उच्च शिक्षा के अंतर्गत आप शिक्षण या रिसर्च दोनों ही क्षेत्र में करियर बना सकते हैं।

रिसर्च में करियर

मनोविज्ञान के तौर पर आप रिसर्च एजेंसियों, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गनाइजेशन या विश्वविद्यालयों में रिसर्च कर सकते हैं। सभी क्षेत्रों के भीतर रिसर्च करियर और भी व्यापक हैं, इसमें सरकारी नीति विकास या उद्योग के लिए काम कर सकते हैं। आप एक चैरिटी या अन्य गैर-लाभकारी संगठन के लिए भी काम कर सकते हैं जो भाषण बाधाओं, मस्तिष्क क्षति, बाल विकास या मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर कानूनी और अवैध दवाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों को हल करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं।

मीडिया और विज्ञापन करियर

मनोविज्ञान डिग्री होल्डरों के लिए मीडिया में भी विविध करियर हैं। मनोविज्ञान स्नातक मानव व्यवहार को लेकर कंपनी के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बता सकते हैं। साथ ही समस्याओं का विश्लेषण करने, ध्यान से सुनने, प्रतिक्रिया देने और सहानुभूति और कारण के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। इस वजह से, प्रबंधन, उत्पादन, शेड्यूलिंग और लेखन सहित सभी विभागों के भीतर मनोविज्ञान स्नातकों की मांग होती है।

मानव संसाधन और संचार करियर

मनोविज्ञान की डिग्री के साथ ह्यूमन रिसोर्स और कम्युनिकेशन करियर भी एक अच्छा विकल्प है। पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध इन भूमिकाओं में कर्मचारी संतुष्टि, व्यावसायिक विकास, प्रशिक्षण, भर्ती, पीआर, पेरोल और आंतरिक संचार जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी करना चाहते हैं क्या है प्रवेश प्रक्रिया

इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी करना चाहते है तो मास्टर्स में न्यूनतम 55% अंक आवश्यक है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन या एम. फिल की डिग्री होनी चाहिए।

अगर आप भी इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी करना चाहते है तो मास्टर्स में न्यूनतम 55% अंक आवश्यक है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन या एम. फिल की डिग्री होनी चाहिए। यह 3-5 साल का कोर्स होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबन्ध, और विभिन्न देशों के बीच सम्बन्ध के कारकों और पहलुओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। अगर आप भी इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी करके राजनयिक के तौर पर काम करना चाहते है तो आइये जानते है इसमें नामांकन के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिये।

योग्यता

- संबंधित विषय में एम फिल की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक होना आवश्यक है।
- विश्वविद्यालयों द्वारा भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5% अंकों की छूट दी जाती है।
- यूजीसी-नेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं भी आयोजित की जाती हैं।
- प्रवेश परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर किया तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

पीएचडी इन इंटरनेशनल स्टडीज के लिए भारत के टॉप कॉलेजों द्वारा अपनाई जाने वाली एडमिशन प्रोसेस इस प्रकार है

- ऑफिशयल वेबसाइट पर जाएं।
- ऑफिशयल वेबसाइट पर जाने के बाद आवेदन फॉर्म भरें।
- फार्म को ध्यान से भरें नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है
- सभी दस्तावेज जो भी मांगे गए है उनको अपलोड करिये।
- ऑनलाइन फॉर्म की फीस जमा करें।
- फार्म को सबमिट करें।

प्रवेश परीक्षा

अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहते है तो प्रवेश परीक्षा में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिट कार्ड जारी किये जाते है। जिनमे परीक्षा की सारी जानकारी होती है। प्रवेश प्रक्रिया सीएसआईआर यूजीसी नेट, एसआईयू पीईटी, एमिटी यूनिवर्सिटी पीईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम पर निर्भर करती है।

प्रवेश प्रक्रिया

परीक्षा परिणाम के लिए आप वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते है, प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में सफल होने के बाद डॉक्टरेट स्तर पर इंटरनेशनल स्टडीज का अध्ययन करने के लिए एडमिशन दिया जाता है।

पीएचडी इन इंटरनेशनल स्टडीज- सिलेबस

- एडवांस्ड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन
- एडवांस्ड रिसर्च मेथड
- फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन
- थिसिस
- शांति और संघर्ष अध्ययन

देश के कुछ टॉप कॉलेज

- झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय
- सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे
- लाजपत राय लॉ कॉलेज
- शिव नादर विश्वविद्यालय
- गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
- रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
- एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा
- कलिंग विश्वविद्यालय
- पंजाब विश्वविद्यालय
- पी.पी. सवानी विश्वविद्यालय
- यूएनओएम, मद्रास विश्वविद्यालय
- गुरु नानक देव विश्वविद्यालय

क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ शौक ही नहीं, करियर भी बन सकता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है एक और करियर, जो है ट्रांसलेटर यानी अनुवादक का। इसके लिए तो अनेक संस्थानों में काफी स्कोप रहता है।

करियर भी बना सकता है क्रिएटिव राइटिंग का शौक

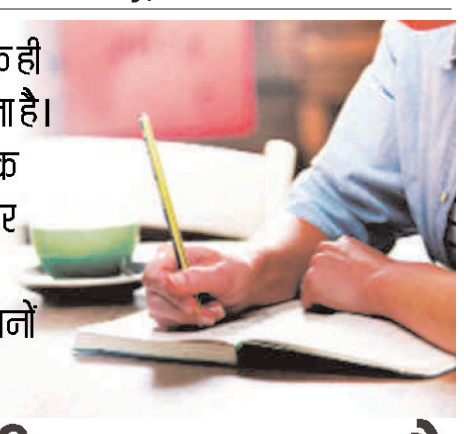

कहां है मांग ?

रेलवे, बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) आदि में अनुवादकों की अच्छी डिमांड रहती है। आप चाहें, तो फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहीं इंटरप्रेटर के रूप में खुद को तैयार करके आप विभिन्न देशों के दूतावासों तथा विदेशी कंपनियों में जॉब पा सकते हैं। यह एक दिलचस्प जॉब है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। अभ्यास बहुत जरूरी लेखक बनने का हुनर कई लोगों में जन्मजात होता है मगर इस हुनर को मांजना बहुत जरूरी है। हर लिखने वाला प्रभावशाली नहीं होता। अगर आप भी बतौर क्रिएटिव राइटर करियर बनाना चाहते हैं, तो सरल, सहज और प्रभावी लिखने का अभ्यास करते रहें। पुराने क्लासिक्स से लेकर नए, प्रमुख लेखकों की किताबें तथा पत्र-पत्रिकाओं मे छपने वाले उनके कॉलम जरूर पढ़ते रहें। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही आपका लेखन निखरेगा। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप सीखें सबसे लेकिन लिखते समय अपनी मौलिक पहचान जरूर बनाए रखें। आपके लेखन में किसी अन्य लेखक की नकल या प्रभाव नहीं दिखना चाहिए।

कहां से पढ़ें ?

यदि आप करियर के तौर पर क्रिएटिव राइटिंग या ट्रांसलेशन को अपनाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप इसके लिए बाकायदा कोर्स कर लें। क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों से किया जा सकता है। वहीं ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर बनने के लिए आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान या किसी अन्य आधिकारिक संस्थान से अनुवाद का कोर्स करना होगा।

अगर आप सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर बेहतर कम्युनिकेशन स्किल का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप अपने करियर को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपकी पर्सनेलिटी का ही हिस्सा है, इसलिए अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए आपको अपनी कम्यूनिकेशन स्किल भी बेहतर करनी होगी।

पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल

कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करना की एक कला है। ये बिल्कुल भी जरूरी नही है कि हर इंसान को बात करने की कला या सही तरीका आता हो। कम्युनिकेशन स्किल का डिग्री और पढ़ाई-लिखाई से भी कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नही है कि हर पढ़े-लिखे और डिग्रीधारी शख्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ही हो। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर इसमें सुधार जरूर किया जा सकता है।

बॉडी लैंग्वेज सही रखें

यह एक तरह का नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बिना कुछ बोले बॉडी के हाव-भाव से सब कुछ कह देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप सामने वाले पर्सन के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं, तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखना जरूरी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा सकते हैं, लोगों से बात करते समय या मीटिंग्स में जेब में हाथ डालकर या हाथों को फोल्ड करने नहीं रखना चाहिए है आपको सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सही तरह से यूज करना चाहिए।

दूसरों की बातें ध्यान से सुनें

अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरों भी बात को भी बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। इससे आप उसकी बातों को अच्छे से समझ सकेंगे। शुरुआत में बात करते समय आपसे कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो गलतियां कम होंगी और आप सही से कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी बात को अच्छे से सुनिए फिर बोलना सीखिए।

सामने वाले को समझें

अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे है, तो आपको उसकी बातों को अच्छे से समझने के साथ उसे भी समझना होगा कि वो आपसे क्या कहना चाहता है। तभी आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। इसलिए पहले सामने वाले पर्सन की बातों को अच्छे से समझें कि वो क्या कहना चाहता है, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है और उसको अच्छे से समझने के बाद आप अपना जवाब दें।

सही शब्दों का प्रयोग करें

किसी से बात करते समय आपको सही शब्दों का यूज करना चाहिए। इसके लिए डेली नये शब्दों को सीखें और उन्हें लोगों से बात करते समय यूज करें। स्टार्टिंग में आपको लोगों से बात करते समय अपनी आवाज को स्लो रखना है और सही शब्दों को बोलना है, बहुत बार ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी में लोग कम्युनिकेशन करते समय गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, आपको धीरे बोलना है और अपने शब्दों को स्पष्ट बोलना है। जिससे सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से समझ सके।

रोज प्रैक्टिस करें

अगर आप दिल से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको डेली कम्युनिकेशन के कुछ वर्ड्स याद करने होंगे और इन याद किये गये वर्ड्स को हफ्ते में 2 बार दोहराना होगा। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ने के बाद इन्हें दोबारा देखेंगे नहीं तो भूल जायेंगे। रोज थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिकेशन पर दीजिए, डेली कुछ नये वर्ड्स सीखिए। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी।

प्वॉइंट टू प्वॉइंट बात करें

चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई अन्य व्यक्ति, किसी से भी बात करते समय ध्यान रखें कि आपको प्वॉइंट टू प्वॉइंट बात करना है। किसी से बात करना होता है तो आपको बिना डरे खुल कर बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे तो जिस प्वाइंट पर आप बात करना चाहते हैं, उसपर नहीं कर पाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति भी कंफ्यूज रहेगा।

आई कांटेक्ट रखें

यह ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाये रखें। इससे हमारी सिंसेरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देता है और साथ ही हमारे इमोशन्स भी साफ-साफ दिखाई देते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफेक्टिव बनती है। वहीं ऐसे बात करते समय आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।

कॉफिडेंट रहें

किसी से बात करते समय कॉफिडेंट रहना जरूरी होता है। यह तभी हो पाएगा जब आप निडर होंगे, श्योर होंगे और जब आप बाहर की आवाजों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में जब भी आप किसी से बात करें, तो अपनी गलतियों से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां होना एक नार्मल बात है, लेकिन जब धीरे-धीरे आप बोलना सीख लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, मीटिंग्स में या कहीं पर भी बोल सकेंगे।

लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के हो सकारात्मक प्रयास

रमेश सर्राफ धमोरा

मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है।

हम 10 दिसंबर को मानवाधिकारों का उत्सव मनाते है। उस दिन की स्मृति में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह घोषणा हमारे समाजों के मानवाधिकार ढांचे की रीढ़ है, जहां हममें से प्रत्येक को बिना किसी भेदभाव के शांति और सुरक्षा के साथ रहने और फलने-फूलने का अधिकार है। 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष की 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना तय किया था। 75 वर्ष पहले पारित हुआ विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र एक मील का पत्थर हैं। जिसने समृद्धि, प्रतिष्ठा व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति मानव की आकांक्षा प्रतिबिंबित की है। आज यही घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बुनियादी भाग है। 10 दिसंबर 2025 को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिज्ञाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 77वीं वर्षगांठ है । 2025 में मानवाधिकार दिवस की थीम हमारी रोजमर्रा की अनिवार्यताएं, तीन सरल सत्यों पर जोर देती हैं। मानवाधिकार सकारात्मक हैं, मानवाधिकार आवश्यक हैं, और मानवाधिकार प्राप्य हैं।

मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के पास हैं। मानवाधिकार मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता हैं। मानवाधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति, राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, काम और शिक्षा का अधिकार और बहुत कुछ शामिल हैं। बिना किसी भेदभाव के हर कोई इन अधिकारों का हकदार है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है। कुछ अधिकार ऐसे होते है जो व्यक्ति को जन्मजात मिलते है। उन अधिकारों का व्यक्ति के आयु, प्रजातीय मूल, निवास-स्थान, भाषा, धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता।

देश के विशाल आकार व विविधता तथा सम्प्रभुता सम्पन्न धर्म-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा तथा एक भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणामस्वरूप भारत में मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमें धर्म की स्वतंत्रता भी अंतर्भूक्त है। संविधान की धाराओं में बोलने की आजादी के साथ-साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अन्दर एवं बाहर आने-जाने की भी आजादी दी गई है। भारतीय परिदृश्य में यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल हैकि क्या वाकई में मनुष्य के लिए चिन्हित किये गए मानवाधिकारों की सार्थकता है।

भारत में 28 सितम्बर 1993 से मानव अधिकार कानून अमल में आया। 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिक और राजनीतिक के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी आते हैं। जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, हिरासत और मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकार। पूरे विश्व में इस बात को अनुभव किया गया है और इसीलिए मानवीय मूल्यों की अवहेलना होने पर वे सक्रिय हो जाते हैं। इसके लिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14,15,16,17,19,20,21,23,24,39,43,45 देश में मानवाधिकारों की रक्षा करने के सुनिश्चित हैं।

कहने में मानवाधिकार शब्द बहुत बड़ा है। क्योंकि मानवाधिकारो से हर व्यक्ति का हित जुड़ा होता है। आज के दौर में कोई भी मानव को उनके वास्तविक अधिकार नहीं देना चाहता है। राजनेता मानव अधिकार की बात तो जोरशोर से करते हैं। मगर जब अधिकार देने की बारी आती है तो पीछे खिसकने लगते हैं। राज नेताओं को पता है कि यदि लोगों को उनके अधिकार मिल गये तो तो उनकी नेतागिरी बन्द हो जायेगी। हमारे देश के संविधान में मानव को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। मगर उन पर अमल नहीं हो पाता है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिये बनाये गये कानून महज कागजो में सिमट कर रह जाते हैं।

इतिहास गवाह है की भारत ने कभी भी संस्कृति, धर्म या अन्य कारकों के आधार पर दूसरों को अपने अधीन करने की कोशिश नहीं की है। भारत एक ऐसा देश है जिसके मूल में मानवाधिकार की अवधारणा है। भारत के लोग मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। भारत विश्व स्तर पर आज भी मानवाधिकार का समर्थन करता रहा है। मानवाधिकार दिवस की नींव विश्व युद्ध की विभीषिका से झुलस रहे लोगों के दर्द को समझ कर और उसको महसूस कर रखी गई थी। किसी भी इंसान की जिन्दगी, आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकार का नाम ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इन अधिकारों की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोडने वाले को अदालत सजा भी देती है।

पूरी दुनिया में मानवता के खिलाफ हो रहे जुल्मों-सितम को रोकने, उसके खिलाफ संघर्ष को नई परवाज देने में इस दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर शख्स को बराबरी का अधिकार देना लोकतंत्र का अहम घटक है। यही वजह है कि आज ज्यादातर सरकार इस अधिकार को कायम करने की कोशिश कर रही है। इंसानी अधिकार हमारे अस्तित्व और दुनिया में आत्मसम्मान से रहने की गारंटी होते हैं। हमारी भौतिक और आत्मिक सुरक्षा बरकरार रखते हुए लगातार तरक्की में अहम होते हैं। इसके अंतर्गत भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण से रक्षा का अधिकार, प्रवास का अधिकार, बाल शोषण, उत्पीडन पर रोक, महिला हिंसा, असमानता, धार्मिक हिंसा पर रोक जैसे कई मजबूत कानून बनाए गए हैं। यही वजह है कि हर लोकतांत्रिक देश मानवाधिकार अधिकारों की सशक्त पैरवी करते नजर आते हैं।

इस दुनिया में जो भी मानव जन्म लेता है उसके साथ उसके कुछ अधिकार भी वजूद में आते हैं। कुछ अधिकार हमें परिवार देता है तो कुछ समाज, कुछ अधिकार हमारा मुल्क देता है, तो कुछ दुनिया। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो या तो अपने अधिकारों से अंजान है या उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर, कभी लिंग भेदभाव के जरिए तो कभी रंग भेद नीति को अपनाकर लोगों के इन अधिकारों को कुचला जा रहा है। हर तबके, हर शहर और दुनिया के कोने-कोने में किसी न किसी वजह से लोगों को बराबरी के हक से महरूम रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में हुई बड़ी से बड़ी क्रांति के पीछे अधिकारों का हनन ही अहम वजह रही है। हमेशा ही अपने अधिकारों के लिए इंसान को लंबी जंग लडनी पड़ी है। दुनिया में तमाम जगह लोगों ने अपन हक की लड़ाई में लाखों कुर्बानियां दी हैं और आज भी बहुत से लोग अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गए और उनको लागू करने या करवाने के लिए प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन वह सिर्फ कागजी दस्तावेज बन कर रह गए हैं। समाज में मानवाधिकारों के होने वाले उल्लंघन के प्रति अगर मानव ही जागरूक नहीं है तो फिर इनका औचित्य क्या है? देखे तो पता चलेगा की कितने मानवाधिकारों का हनन मानव के द्वारा ही किया जा रहा है। मानव के द्वारा मानव के दर्द को पहचानने और महसूस करने के लिए किसी खास दिन की जरूरत नहीं होती है। अगर हमारे मन में मानवता है ही नहीं तो फिर हम साल में पचासों दिन ये मानवाधिकार का झंडा उठा कर घूमते रहें कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

सरकार भी मानवाधिकारो का हनन रोक पाने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही है। देश में आये दिन मानवाधिकार हनन की घटनायें घटित होती रहती है। मगर सरकारी स्तर पर शख्त कार्यवाही अमल में नहीं लायी जाती है। जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति पर रोक लग सके। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का लगातार हनन होता रहता है।

संपादकीय

बाबरी बनाम राम मंदिर

तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कुछ मुस्लिम चेहरों के साथ बाबरी मस्जिद की नींव रखी, तो दूसरी तरफ बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, बाबा बागेश्वर और कई साधु-संतों ने, एक व्यापक जन-सैलाब के साथ, 'गीता पाठ' किया। बाबरी मस्जिद से 11 किमी की दूरी पर 'बहरामपुर' में राम मंदिर बनाने का उद्घोष किया गया। इन दोनों फैसलों और कर्मकांडों का धार्मिक आस्था से कोई सरोकार नहीं है। ये सांप्रदायिक, हिंदू बनाम मुसलमान, जमावड़े थे, जिनकी मानसिकता में अप्रैल-मई, 2026 के विधानसभा चुनाव उमड़-घुमड़ रहे थे। बेशक प्रभु श्रीराम समूचे भारत के जनमानस के सबसे अधिक स्वीकार्य और पूजनीय आराध्य हैं। राम के जीवन-चरित पर सबसे अधिक, प्रमुख भाषाओं में, 'रामायण' का सृजन किया गया है। यदि हमारे आराध्य का एक और मंदिर बनाया जाता है, तो वह विवादास्पद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू 'मूर्ति पूजक' हैं, लेकिन श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में आराध्य का भव्य मंदिर बन चुका है। मंदिर के शिखर पर सनातन की प्रतीक 'धर्म-ध्वजा' भी सुशोभित की जा चुकी है। देश भर से लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य श्रीराम के दर्शन करने और मत्था टेकने अयोध्या जा रहे हैं। राम मंदिर का सम्मान किसी तीर्थ-स्थान से कमतर नहीं है, लिहाजा एक और राम मंदिर के उद्घोष का औचित्य क्या है? देश में आज भी प्रभु राम के असंख्य मंदिर हैं, जहां अनवरत पूजा-पाठ जारी है। बेशक राम के नाम पर ध्रुवीकरण और सामुदायिक लामबंदी जरूर की जा सकती है। चुनाव के मद्देनजर उनका महत्व भी निर्णायक है। यकीनन हिंदुओं अथवा ऐसे आस्थावानों के ध्रुवीकरण से भाजपा को चुनावी फायदा सर्वाधिक होता रहा है। स्वतंत्र भारत में बाबर जैसे विदेशी आक्रांताओं के स्मारक के तौर पर मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत अब एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है, उसमें बाबर का स्मारक स्वीकार्य नहीं है। मुस्लिम मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो सरकार से बाकायदा इजाजत लें और पैगंबर मुहम्मद के नाम पर मस्जिद बनाएं। किसे आपत्ति होगी? हालांकि राजधानी दिल्ली में 'बाबर रोड' आज भी मौजूद है। ऐसे और भी स्मारक बाबर के नाम पर देश में होंगे, लेकिन नए प्रयास, नए शिलान्यास, नए निर्माण को नहीं होने देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कथित बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखने देनी चाहिए थी। भाजपा के जो चेहरे चीखा-चिल्ली कर बाबरी का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी नींव का पुरजोर विरोध करना चाहिए था। मुख्यमंत्री को अपने ही बागी विधायक को गिरफ्तार कराना चाहिए था, लेकिन बाबरी मस्जिद की प्रतीकात्मक नींव रख दी गई और वह तबका अपनी सांप्रदायिकता में कामयाब रहा। ममता को मुर्शिदाबाद की 24 विधानसभा सीटों पर 65 फीसदी से ज्यादा मुसलमानों के वोट की चिंता थी, तो ममता हिंदुओं के वोट भी छोड़ नहीं सकती थी। बंगाल में 35-40 फीसदी हिंदू वोट ममता की पार्टी के पक्ष में भी जाते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने विधायक को निलंबित ही किया।

चिंतन-मनन

चैतन्य रहें

एक बार दो देवताओं में विवाद हो गया कि भाग्य बड़ा है या पुरूषार्थ? विवाद हर व्यक्ति के मन में पैदा होता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो। निश्चित हुआ, परीक्षा करें। एक देवता ने कहा- देखो! भाग्य बड़ा नहीं होता, पुरूषार्थ बड़ा होता है। दूसरे ने कहा- नहीं! उस आदमी को देखो। तुम्हें साक्षात प्रमाणित करूंगा कि पुरूषार्थ बड़ा नहीं होता, भाग्य बड़ा होता है। पति-पत्नी जा रहे थे। देवता ने रास्ते के बीच रत्नों का ढेर लगा दिया। रत्न ही रत्न बिखेर दिए। जब आस-पास आए, पत्नी ने कहा- अभी तो हमारी आंखे अच्छी हैं, हम देख सकते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देता है। कभी ?सा भी हो सकता है कि बुढ़ापा आने के साथ-साथ हमारी आंखें चली जाएं, हम अन्धे हो जाएं। फिर काम कैसे चलेगा? पति ने कहा - परीक्षा कर लें। देखें, कैसे काम चलेगा? दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली। दोनों चले। जहां रत्न बिखरे हुए पड़े थे, ढेर लगा था आस-पास में, उससे आगे निकल गए। कुछ आगे जाकर पति बोला- आंखो के बिना काम तो चल जाएगा, ?सी कोई बात नहीं है। खोल लो पट्टी। पट्टी खोल ली। देवता ने कहा - देखा तुमने! भाग्य में नहीं था, कुछ नहीं मिला। भाग्य बड़ा है पुरूषार्थ से। भाग्य और पुरूषार्थ की चर्चा को हम छोड़ दें किन्तु इस बात को हम नहीं छोड़ेंगे कि जब तक आंख पर मूर्च्छा की पट्टी बंधी हुई है, तब तक हमारे आस-पास में, हमारे सामने, दाएं-बाएं, चारों तरफ जो सम्पदा बिखरी पड़ी है, उसका हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हम उस सम्पदा से अनजान रह जाते हैं।

75 साल बाद संसद में वंदे मातरम की राजनीति?

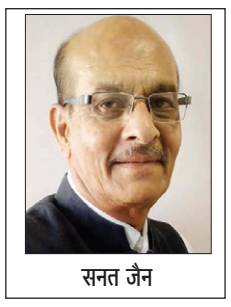

सनत जैन

नई पीढ़ी जानेगी वंदे मातरम का इतिहास, मां किसी से भेदभाव नहीं करती...

स्वतंत्र भारत की संसद में 75 वर्षों के बाद 'वंदे मातरम' पर हुई चर्चा पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक राजनीतिक प्रयास के रूप में शुरू हुई। वंदे मातरम की यह चर्चा एक गीत या नारे तक सीमित नहीं रही। यह बहस प.बंगाल के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण, उसकी सांस्कृतिक चेतना और एकता के भाव को समझने का अवसर भी बन गई। संसद में सभी राजनीतिक दलों और सभी सांसदों ने एकजुट होकर वंदे मातरम के पक्ष में बढ़-चढ़कर अपने विचार व्यक्त किये।वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है। बल्कि वह स्वर है, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों लोगों के हृदय में देशभक्ति की ज्योति जगाई थी। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत आज भी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके बोल हर किसी को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कर देते हैं।संसद में इस विषय पर हुई चर्चा का सबसे बड़ा महत्व यह है, नई पीढ़ी को वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को जानने और समझने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और तकनीक की दुनिया में व्यस्त है। ऐसे विषय पर संसद में जो सार्थक बहस हुई है। वर्तमान पीढ़ी को सोशल मीडिया के माध्यम से बेहतर तरीके से स्वतंत्रता के इतिहास और वर्तमान में प.बंगाल के चुनाव में इस नारे का क्या महत्व है। यह जानने का अवसर मिलेगा। युवा पीढ़ी यह जान सकेगी राष्ट्र की पहचान केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि उसके गौरवपूर्ण अतीत से भी बनती है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को इस नारे ने विफल कर दिया था। धर्म, भाषा, प्रांत, गरीब और अमीर सब इस नारे से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। संसद में बहस के दौरान यह बात भी उभरकर सामने आई। 'मां' किसी से भेदभाव नहीं करती है। वंदे मातरम में जिस मां की वंदना की गई है। वह भारत माता है।जो अपने सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के समान दृष्टि से देखती है। चाहे वह किसी भी भाषा, धर्म, जाति या किसी भी क्षेत्र से हो। यह गीत किसी एक वर्ग, समुदाय या धर्म का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। वंदे मातरम को संकीर्ण नजरिये से देखना ना केवल इसके भाव को सीमित करता है। बल्कि राष्ट्रीय एकता अखंडता और भारतीय संस्कृति को भी चोट पहुंचाता है।

हाल के वर्षों में वंदे मातरम को लेकर समय-समय पर राजनीतिक लाभ के लिए विवाद खड़े होते रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इसे विवाद का विषय बना रहे हैं। संसद में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वंदे मातरम के इस नारे ने स्वतंत्रता की जो लो आम जनमानस के बीच में जगाई थी। सबने बढ़ चढ़कर इस नारे के औचित्य को समझाया।संसद में हुई बहस ने यह स्पष्ट किया, देशभक्ति किसी पर थोपी नहीं जा सकती है, अभिव्यक्ति के माध्यम अलग-अलग भी हो सकते हैं। यह दिल से उपजने वाली भावना है। वंदे मातरम का सम्मान करना और उसके भाव को समझना सभी नागरिक अच्छी तरह से जानते हैं। कोई भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ना नहीं चाहता है। हां अभिव्यक्ति के तरीके जरूर अलग-अलग हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले इसे विवाद का विषय बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरूरत इस बात की है, हम वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीति से ऊपर उठकर देखें। यह गीत सारे भारत को एक साथ जोड़ता है। इसका एक-एक शब्द सारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। संसद में हुई बहस नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका, संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने में संसद की यह चर्चा सार्थक साबित होगी। वंदे मातरम के नारे का जन्म पश्चिम बंगाल से हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में इसके नारे देश के सभी प्रांतों मे गूंजे। दुनिया में सैकड़ो रामायण विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। सब में अलग-अलग तरीके से राम का वर्णन किया गया है। ठीक उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वंदे मातरम गीत को प्रत्येक भाषा में अलग-अलग तरह से इसे विभिन्न बोल और विभिन्न भाषाओं में अलग-अलग संगीत की धुन में गाया गया है। वंदे मातरम में प्रत्येक गीत और संगीत में एक सा भाव है। वंदे मातरम के इस नारे से हमने स्वतंत्रता पाई है। अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो की नीति को सफल नहीं होने दिया। जैसे ही इस नारे ने भारत को एकजुट किया। अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा। संसद में वंदे मातरम विषय पर जो बहस हुई है। प्रत्येक सांसद ने वंदे मातरम के पक्ष में बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। वंदे मातरम को लेकर जो राजनीति पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तारतम्य में प्रयास किया जा रहा है। उसमें कितनी सफलता मिलेगी, यह तो भविष्य ही तय करेगा। संसद में जिस तरह से सांसदों ने वंदे मातरम को लेकर ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। संसद में हुई बहस ने नई पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन और वंदे मातरम के महत्व को समझाने में जरुर मदद की है। प. बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का जो प्रयास वंदे मातरम के माध्यम से करने के प्रयास को कितनी सफलता मिलेगी? यह कहना मुश्किल है।

गोवा हादसा: झुलसती संवेदनाएं और नाकाम होती व्यवस्था

ललित गर्ग

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उतनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं।

गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ, समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का रखरखाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फाइलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बीते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं। नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं-'दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा', 'उच्च स्तरीय जांच की जाएगी', 'मुआवजा दिया जाएगा', लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। व्यवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मूल्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं; प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उत्तरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर।

गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जी सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि हमने नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी निकट ही खड़ी है। हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल जान-माल को ही क्षति नहीं पहुंचातीं, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नया और विकसित बनने के आकांक्षी भारत में नियम-कानूनों की हर स्तर पर उपेक्षा होती है और इस देश में जिम्मेदारी के साथ कोई काम मुश्किल से ही किया जाता है। मानकों और सुरक्षा उपायों की रेगुलर चेकिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ल्ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कीमत केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था में भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी और जब तक नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के नाम पर मौतें होती रहेंगी। गोवा का नाइट क्लब हादसा केवल आग नहीं-हमारे विवेक, शासन और मानवता की विफलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे भूलें या इसे परिवर्तन की शुरूआत बनाएं।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

India-Russia ties poised to gather pace

The state visit by Russian President Vladimir Putin to India drew heightened international attention, which gave it the colouring of a geopolitical event. Three European ambassadors assigned to Delhi from France, Germany and the UK even resorted to pamphleteering to smear Russia, compelling a rare rebuke by the government. In the event, though, Prime Minister Narendra Modi and Putin kept the focus on the bilateral content, with a long-term perspective.Although the presence of the ghost at the banquet would have been on their minds, neither Modi nor Putin showed any signs of it. In fact, Putin embarked on the journey to Delhi right after his momentous 5-hour negotiations in the Kremlin with US President Donald Trump's special envoy Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner, which have held out hopes that guns may soon fall silent in the battlefields of Ukraine and promises a historic breakthrough in the adversarial Russian-American relationship that has posed formidable challenges lately to Indian diplomacy.

To be sure, the Delhi summit was held in the backdrop of a tumultuous shift of tectonic plates in the alignment of major powers, especially Russia and India. In his first public remarks with Putin, Modi went straight to the point, saying India was anything but 'neutral' in the Ukraine situation and stood for peace. It was a bold articulation of support for the coordinated efforts by Putin and Trump to bring the war to an end, the diabolical moves by the European Union and the Kiev regime to smother the nascent peace process notwithstanding.By coincidence, perhaps, Trump chose Friday, even as Putin's visit was under way, to unveil the new National Security Strategy (NSS) of his presidency, which painted European powers as weak and raised doubts about their long-term reliability as partners; reinforced the 'America First' philosophy espousing non-intervention overseas; and called for shifting US military assets to the Western Hemisphere, "away from theatres whose relative import to American national security has declined in recent decades".

The NSS stressed improved ties with both Russia and India. On the one hand, it messaged that ending the Ukraine war is a core US interest to "reestablish strategic stability with Russia", while on the other hand, it stated the Trump administration's determination to "improve commercial (and other) relations with India to encourage New Delhi to contribute to Indo-Pacific security".Conceivably, Moscow and Delhi could anticipate the drift of the forthcoming NSS document presaging an imminent shift in the Trump administration's strategic calculus. It must have been a daunting challenge to choreograph a summit with a superpower in such a fluid setting, and it probably accounted for the anti-climactic look of the Modi-Putin summit. The joint statement, titled 'INDIA-RUSSIA: A Time-Tested Progressive Partnership, Anchored in Trust & Mutual Respect', prudently steered clear of the geopolitical convulsions in the international environment. The entire turf of defence ties lies submerged. There was no trace of 'anti-Americanism' in the summit's proceedings.Nonetheless, the joint statement firmly reaffirmed the further strengthening of the special and privileged strategic partnership and "emphasised the special nature of this long-standing and time-tested relationship, which is characterised by mutual trust, respect for each other's core national interests and strategic convergence". It asserted that "as major powers with shared responsibilities, this important relationship continues to be an anchor of global peace and stability that should be ensured upon the basis of equal and indivisible security".

Suffice to say, the joint statement unequivocally rejects the Western pressure on India to sever its relationship with Russia. The relevant paragraphs defiantly state, "The leaders positively assessed the multi-faceted mutually beneficial India-Russia relations that span all areas of cooperation, including political and strategic, military and security, trade and investment, energy.

The Army's ethic

Unity in diversity, anchored in the hierarchy of faith, oath and purpose

THERE are moments when a court judgment does more than settle a dispute; it restores direction. The Supreme Court's ruling upholding the dismissal of an officer who declined to accompany his soldiers into a regimental place of worship is one such moment. It reaffirms a truth soldiers have always lived and democracies must continually reinforce: a Republic stands on the strength of its institutions, and institutions stand on the integrity of their covenants.In public debate, and in some commentary, the case has been misconstrued as an opportunity to revisit long-standing military practices. This interpretation misses the central point. This was not a dispute about ritual but about cohesion, duty and the constitutional architecture of a plural Army.

It arose in a regiment where a mandir and a gurdwara stand side by side and have long served as a unified Sarva Dharma space. The officer refused to enter, asserting that his faith did not permit stepping into the sanctum. Across the Army, such spaces do not demand belief; they affirm coexistence. They ask only that cohesion not fracture in the presence of diversity. Even after counselling and a pastor's reassurance that entering would not compromise his faith, he continued to stand apart.

Unity in diversity has never meant fragmenting units or engineering representation to a diktat. The Army has never understood unity as a matter of numbers, ratios or prescribed compositions. Whoever stands together, wherever they come from and in whatever proportion they appear, is also unity, because cohesion is not arithmetic; it is lived experience. This is why the suggestion made in some commentary that the case should prompt a revisiting of class compositions or regimental practices misses the point entirely. Unity in the Army is not constructed by external design; it is sustained by shared duty, shared danger and the oath that binds every soldier to the next.One incident, however visible, cannot be used to reopen or reinterpret an institutional architecture. A refusal of duty calls for understanding, not redesign, and certainly not redesign by those unfamiliar with the letter, the alphabet and the grammar of the very ethic they seem to reinterpret. The Army's practices were not shaped in abstraction; they were forged by the realities of land warfare, the demands of cohesion and the lived experience of diverse units fighting as one. To treat a single case as an opportunity for structural change is to mistake a moment for a mandate and an incident for an institution.Some have asked whether the reaction would have differed had the officer belonged to a majority community. This question misreads the uniform. The Army does not weigh identity; it upholds obligation. A breach of a unifying duty is identical regardless of who commits it. The ethic is the same for one or for many, for minority or majority, because the moment identity enters the calculus, cohesion exits it. This judgment is therefore not about who the officer was. It is about what the institution must remain.The Supreme Court upheld his dismissal not because it doubted his sincerity, but because it recognised that belief cannot outrank duty in the profession of arms. A lawful regimental practice had been set aside by personal interpretation. In a force where unity is operationally non-negotiable, that constituted indiscipline. The Army acted within its mandate; the court upheld this because it strengthened the constitutional spine of a force that serves without favour or fear.To understand why belief cannot outrank duty, one must recall the grammar of soldiering. The letter of land warfare has never changed: hand to hand, bayonet to bayonet, man to man, tank to tank. The closeness of battle leaves no room for fracture. The alphabet is the Army's diversity of arms and service. The grammar is the assault, the eviction, the capture and the hold, the unforgiving syntax of land battle that demands unbroken cohesion. Through letter, alphabet and grammar, the constant is the man: his instinct, his motivation and his enduring code, Naam, Namak, Nishan.Unity in diversity is not an aspiration; it is an operational necessity. Whether a unit is all class, mixed class or fixed class, officer leadership is always mixed. The Sarva Dharma Sthal exists for this architecture. It is not ritual; it is a post-Independence institutional design that ensures every soldier can stand with his comrades even when they do not worship alike. It is the Army's own indigenous grammar of unity, a space where identity dissolves into duty.This judgment matters because the Army is the Republic's most visible school of constitutional citizenship. It is where language, region, caste and creed appear in every company line yet do not determine privilege or precedence. The Army's ethic is not the erasure of difference but the refusal to let difference become division. It allows a million identities to wear one uniform without asserting themselves at the cost of another.This ethic is not decorative. It is the foundation of discipline, trust and operational integrity. A commander cannot stand apart from his men at the very moment that symbolises collective identity. Nor can a unit remain cohesive if individuals reinterpret institutional practice through personal preference. The court recognised that such a path would weaken a secular, apolitical force. The Army's secularism protects the rights of all by ensuring that none asserts primacy.

There is also a reminder for the Army. Cohesion is not guaranteed by tradition alone. It is renewed each time the oath is placed above interpretation and each time the collective ethic is upheld without hesitation. The Army does not choose belief for its soldiers; it ensures belief does not fracture the centre.

In an age when societies struggle to hold their balance, when noise outruns nuance and identity outruns empathy, the Indian Army's ethic becomes a national anchor. It shows that coexistence is a daily act, not an ideal. It shows that difference can be held without hierarchy and common purpose can transcend inherited lines. It shows that fidelity to the covenant steadies the institution in moments of strain.By upholding the Army's decision, the Supreme Court has reinforced a principle that has carried India through wars, upheavals and uncertainty. The centre that holds is not built of stone or ceremony. It is built of fidelity to the covenant that binds a million soldiers into one. When that covenant is upheld, the Republic stands steadier, the institution stands clearer, and the message to every rank remains unmistakable: unity in duty is not negotiable.

Karnataka Congress truce holds, crisis unsolved

Camp politics and indiscipline have long plagued the Congress; groupism and loose remarks by followers have kept Karnataka's political pot boiling

The joust for power in Karnataka may have paused, but tension between the two main players of the Congress remains. With the government completing half its term in November, the leadership crisis reached a breaking point. Two breakfast meetings between Chief Minister Siddaramaiah and his deputy D K Shivakumar brought little clarity on whether power will change hands soon. While koli (chicken) curry and Cartier watches dominated media and opposition chatter, the outcome stayed hazy. The leaders have left the decision to the high command, insisting they remain "brothers" who will work together for the state and aim to win the 2028 elections. For now, hostilities have cooled due to other pressures: the winter session in Belagavi, where an aggressive opposition is set to corner the government over the power tussle, and the Congress's recent drubbing in Bihar.The legislature session beginning Monday promises to be stormy, with the Bharatiya Janata Party and Janata Dal (Secular) likely to raise issues concerning sugarcane and maize farmers, procurement centres and compensation for crop losses. Corruption and the caste census will also take centre stage. The BJP plans a massive protest, a padayatra and a 'Grama Vastavya' led by B Y Vijayendra and R Ashoka to reach rural voters and highlight local grievances. The government is expected to take up 33 Bills, including the contentious Karnataka Hate Speech and Hate Crimes (Prevention and Control) Bill,

2025. Given its internal divisions, the BJP wouldn't want to pass up a chance to attack the Congress over the CM tussle and its impact on governance.Camp politics and indisipline have long plagued the Congress; groupism and loose remarks by followers have kept Karnataka's political pot boiling. Ministers shuttling to Delhi, second-rung leaders declaring ambitions, and religious and community heads commenting on power equations have all hurt the party's image. Yet the Congress's strength in Karnataka lies in its two top leaders playing complementary roles—Siddaramaiah as a mass leader and Shivakumar as the organisation's anchor. The party has faced similar infighting in Punjab, Rajasthan and Madhya Pradesh, and its inability to manage competing power centres led to its collapse in those states. Voters expect stability and performance, and cannot be taken for granted. The Congress leadership must craft a strategy to keep its Karnataka unit united or risk losing the state as well.

Lessons from yesterday

While growing up, I witnessed women struggling to earn their keep by balancing education and the heavy share of household work. One maintained a brave front, while the other continued with an iron resolve of loathing self-pity. This mirrored a society where faith, too, can fail

Social media had some wounding snippets of news this week: a bridegroom cruelly trolled for being dark, young people despairing of getting an education, and parents working themselves to the bone for their children's sake. It made me want to share some personal history that reflects the ongoing struggle for respect and opportunity in our society, and how faith can fail.My paternal grandmother, Lalita, was widowed at twenty-six. She and her children, my father and his elder sister Kanthi, were sent to her brothers as poor relatives. My father got everything, but the uncles did not think it necessary to educate Kanthi. Nevertheless, when Kanthi was eight, Lalita requested that she be sent to school so that she could earn her living one day.The uncles said she would have to be married, but nobody suitable would marry a fatherless girl without money, so they would have to find Kanthi some poor man willing to take her for free. They said it was enough if she could read and do household accounts.Tripurasundari, Lalita's mother, said nobody would want to marry Kanthi for being dark-skinned, since she was born brown in a pink family. She vehemently opposed Kanthi's education more than her sons did. Ringed by dragons, Lalita politely asked them not only to send Kanthi to school but also to let her have music lessons.This gave the uncles a ladder to climb down without losing face. They said Kanthi could either go to school or have music lessons. To pacify their mother, they also said Kanthi had to get the highest marks in class each year if she wanted to go to the next one.There was nowhere that Kanthi could study peacefully, and she was frequently interrupted by her grandmother for a new chore. Tripurasundari, a sore loser, never stopped saying how dark Kanthi was, a burden on Earth with her lack of looks and dower. Kanthi silently swore never to get married. Later, despite immense family pressure, she held by that decision.Kanthi was not always the first in class, but she pushed herself hard so she never slipped below the top five. If Lalita caught Kanthi reading a storybook, she beat her with the visiri kattai, the wooden handle of her palmetto fan. Lalita had paid Kanthi's school fees with her pride and did not intend to let her squander her chance. This pressure to escape indignity through study ruled Kanthi's life. Going to college, too, was an epic struggle. Her professor at Madras University, Malcolm Adiseshiah, encouraged her. Eventually, she taught economics at no less than Delhi University.Lalita and Kanthi earned their keep, and my father's, by doing a heavy share of housework. Lalita maintained a brave front, while Kanthi said with iron resolve, "I loathe self-pity."

The Freedom movement had begun to stir up the Madras Presidency, the oldest bastion of British rule in India. The uncles were pro-British and disliked political opinions in women. So, Kanthi and Lalita spoke of it covertly, for Lalita was intensely nationalistic.Lalita had somehow taught herself to read English, Hindi and Urdu, and used

part of her scant allowance to buy newspapers in all three languages. She began to keep a secret political diary that Kanthi read only after her death. In it, said Kanthi, she had poured out all her hopes and apprehensions about the social and political future of the country, its communal rifts, and her own absolute abhorrence of caste and gender discrimination.Tripurasundari scoffed at Lalita's reading, especially of English books, but could not really object since Lalita sat down to read only in the afternoon after completing any number of household chores.A cousin from Vellore began to visit in the early 1940s. A well-read and highly intelligent lady, she was married to a rich but uneducated man, who liked to drink and party with the men of his neighbourhood.This lady had not been allowed to study but had taught herself to read. She had a keen interest in Marxism, and in Lalita she found a kindred spirit. She came by often, and they would read the Communist Party paper Janasakti. They secretly procured P Jeevanandham's banned Tamil translation of Bhagat Singh's essay Why I Am an Atheist, which they hid under a newspaper cover.Lalita and her cousin spent hours discussing politics at the temple, the only place they could visit freely. It is a piquant thought that these two outwardly meek women sat in a corner of the open courtyard of a temple as the safest place in which to discuss Marxism, atheism and caste.Lalita introduced her cousin to Dr Samuel, a Tamil Christian lady doctor known as 'Apathikaari Amma', the woman apothecary. Dr Samuel gave Lalita a picture of Baby Jesus and Mother Mary, which she kept in her puja corner, in accordance with the ingrained Hindu belief that 'God is One', next to a picture of her beloved Kanchi Kamakshi. Kanthi, however, turned atheist, disgusted by the cruelty of 'believing' society.When my father found employment and took Lalita away to hired lodgings in Madras, she took a sweet-natured Dalit couple in as part-time help.

Proposed insurance ombudsman rules: What policyholders should know

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) recently released the Draft Internal Insurance Ombudsman Guidelines, 2025. These rules propose a new accountability structure inside insurance companies to speed up dispute resolution and reduce harassment of consumers.

New Delhi.(Agency)

After years of rising insurance complaints, delayed claim settlements, and growing anger over rejected payouts, the regulator has finally put a tighter grievance framework on the table.The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) recently released the Draft Internal Insurance Ombudsman Guidelines, 2025. These rules propose a new accountability structure inside insurance companies to speed up dispute resolution and reduce harassment of consumers.It is important to note that these are still only proposed rules and not law yet. The guidelines will take effect only after final notification and will apply three months after that. If implemented in their present form, they could significantly change how insurance complaints are handled in India.

WHY IRDAI DECIDED TO STEP IN

IRDAI has acknowledged in the draft that as insurance coverage expands, policyholder expectations rise. When those expectations are not met, they turn into formal complaints. Despite existing grievance systems, many genuine disputes remain unresolved because insurers still end up reviewing their own decisions.The proposed framework attempts to correct this conflict by placing an independent review authority inside every insurer.

WHO WILL BE THE INTERNAL INSURANCE OMBUDSMAN

Under the proposal, every insurer that has

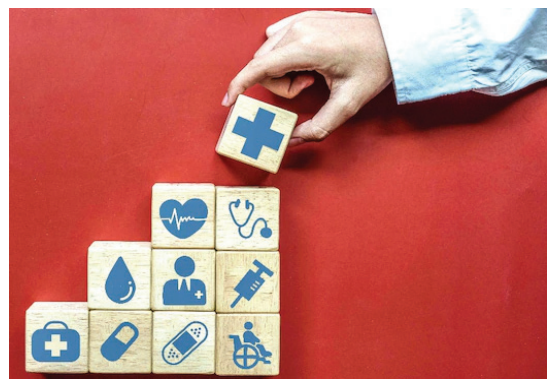

completed three years of operations will be required to appoint an Internal Insurance Ombudsman. Reinsurers are excluded. The officer must have at least 20 years of experience in the insurance sector, must have held a senior role, and must not be a present or former employee of the insurer or its group companies.The appointment will be for a fixed term of three years, extendable once, or until the age of 70, whichever is earlier. The salary must be entirely fixed, with no performance-linked incentives. The purpose is to ensure that grievance decisions are free from business pressure.

NEW POWERS INSIDE INSURANCE COMPANIES

The Internal Ombudsman will become the highest internal grievance authority within the company. Under the draft, this officer will have the power to decide complaints involving amounts up to Rs 50 lakh. The process will first attempt settlement through conciliation or mediation. If that fails, the ombudsman will pass a reasoned order on the merits of the case.

Sliding rupee, liquidity crunch: Why Dalal Street is suddenly feeling the heat

New Delhi.(Agency)

Dalal Street is no stranger to turbulence, but the unease gripping the market right now feels different. This is not the frenzy of panic-selling or the drama of a global shock. It is the quieter, more unsettling churn of uncertainty.As the rupee slides and easy money dries up, investors are beginning to pull back, and the Sensex and Nifty are feeling the heat.In the past few sessions, benchmark indices have come under sustained pressure as selling deepened across key sectors such as banking, IT, metals and rate-sensitive stocks. What began as routine profit-booking has now taken the shape of a broader risk-off trade.According to Akshat Garg, Head of Research and Product at Choice Wealth, the nervousness in the market is rooted in a clear macro shift rather than any sudden deterioration in corporate earnings.Dalal Street isn't nervous without reason. The market is reacting to a mix of weakening liquidity and a sliding rupee, and together they are creating a clear risk-off undertone," Garg said.

RUPEE'S SLIDE DRIVING UNCERTAINTY

A softer rupee rarely goes unnoticed by equity markets. When the currency weakens sharply, it immediately raises worries around imported inflation,

squeezes corporate margins for import-heavy sectors and increases the likelihood of intervention by the Reserve Bank of India.Garg said this is exactly what is now unsettling investors. "Whenever currency volatility spikes, equities start pricing in uncertainty, not fundamentals, and that's exactly what we're seeing," he said.A weakening rupee also changes how foreign investors assess risk. Currency losses begin to compound equity risk, making Indian assets less attractive in the short term and adding to selling pressure just when markets are already fragile.

FII SELLING CREATES LIQUIDITY VACUUM

For months, abundant liquidity ensured that every market dip was quickly bought. That comfort has now faded.

On the liquidity front, Garg pointed out that the recent withdrawal of systemic liquidity and the cautious stance of foreign portfolio investors have taken away that easy support.The 'easy bid' that was supporting every dip is no longer there," he said.When money becomes selective, valuations start getting questioned, and even minor negative news can trigger outsized reactions. This is exactly what markets are witnessing now.

Domestic investors are still showing resilience, but even their behaviour is changing. Instead of chasing the broader index, flows are becoming increasingly stock-specific, focusing on companies with stronger balance sheets and clearer earnings visibility. The era of blind index buying, for now, appears to be on pause.

Sensex opens 350 points lower, Nifty below 25,900; Kotak Bank down 1%

MUMBAI. (Agency)

Benchmark stock market indices continued their downward slide, extending their negative run from the last session as US President Donald Trump threatened fresh tariffs.The S&P BSE Sensex lost 400.82 points to 84,701.87, while the NSE Nifty50 lost 134.80 points to 25,825.75 as of 9:24 am.Dr. VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments Limited, said that failure of the market to hold on to the recent all-time high and absence of fresh triggers for a rally have resulted in some sort of fatigue among investors.The fact that vast majority of retail investors haven't participated in this narrow rally dominated by a few largecaps, makes the retail disillusionment heavy," he added.The market opened weak on Monday, with only a few stocks managing to stay in the green while most of the Sensex pack slipped into the red.Among the early gainers, Hindustan Unilever led the list with a rise of 0.43%, followed by Bharti Airtel which inched up 0.25%. Titan gained 0.05%.On the downside, the market saw a sharp fall across several heavyweight counters, signalling broader pressure on sentiment. Asian Paints was the biggest loser, dropping 3.38%. Trent followed with a fall of 2.06%, and Mahindra & Mahindra slipped 1.16%. Tata Steel was down 1.16% as well, while Tata Consultancy Services declined 1.12%. The widespread red across sectors pointed to a market under stress, with investors turning cautious in early trade."Even when the Nifty set a new record, 320 stocks in NSE 500 were trading below their peaks leaving the retail investors with portfolios dominated by mid and small caps unhappy.

Consequently we are seeing further selling in the mid and smallcaps pushing their prices down, while the strong largecaps which led this rally are remaining resilient," said Vijaykumar."Briefly, what we are witnessing now is fundamentals exerting influence on the market. Overvalued stocks in the mid and smallcap segments are getting dumped impacting their share prices. There is some more time for this trend to play out. Further correction in midcaps will open up opportunities for long-term investors to slowly accumulate high quality growth stocks in this segment. Defence stocks now offer value," he added.

IMF Lists India's UPI As World's Largest Real-Time Payment System

New Delhi.(Agency)

The International Monetary Fund (IMF) has recognised India's Unified Payments Interface (UPI) as the world's largest retail fast-payment system by transaction volume, the Parliament was informed on Monday.

Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary told the Lok Sabha, in a written reply to a question, that this fact has been highlighted in the IMF's report on 'Growing Retail Digital Payments (The Value of Interoperability)' dated June 2025.Further, as per the ACI Worldwide report on 'Prime Time for Real-Time' 2024, UPI tops the global list with a 49 per cent share in the global real-time payment system and a transaction volume of 129.3 billion. Brazil is placed in the second position with a market share of 14 per cent and a transaction volume of 37.4 per cent,

followed by Thailand in the third spot with a market share of 8 per cent and a transaction volume of 20.4 billion. China figures in the fourth place with a market share of 6 per cent and transaction volume of 17.2 billion.The minister further stated that in order to support small-scale merchants in adopting digital payment systems, including UPI, various initiatives have been taken up by the government, the Reserve Bank of India (RBI), and the National Payments Corporation of India (NPCI) from time to time. These, inter alia, include an incentive scheme for promotion of low-value BHIM-UPI transactions, and the Payments Infrastructure Development Fund (PIDF), which provides grant support to the banks and fintechs for deployment of digital payment infrastructure (such as POS Terminals and QR codes) in tier-3 to 6 centres.

As of October 31, 2025, approximately 5.45 crore digital touch points have been deployed through PIDF in tier-3 to 6 centres. Further, as of FY 2024-25, a total of 56.86 crore QR were deployed to approximately 6.5 crore merchants, the minister said.The Government, the RBI, and the NPCI have initiated deepening digital transactions through RuPay and UPI across businesses, including public services, transport, and e-commerce platforms on a nationwide basis.

Gold, Silver Open Flat Ahead Of US Fed Policy Outcome; Gold Unchanged At Rs 1,29,978 Per 10 Grams

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold February contracts were unchanged at Rs 1,29,978 per 10 grams during early trade.

Mumbai.(Agency)

Gold prices were steady in early trade on Tuesday, as investors stayed cautious ahead of the US Federal Reserve's interest rate decision.

On the Multi Commodity Exchange (MCX), gold February contracts were unchanged at Rs 1,29,978 per 10 grams during early trade.In the domestic market, MCX Gold (Feb) is trading near Rs 1,29,952, closely tracking the global uptrend while also receiving support from rupee weakness," market experts said."The Rs 1,29,200 region continues to act as a key short-term support. As long as this level holds, the path remains open toward the Rs 1,30,000–Rs 1,31,000 resistance zone," analysts stated.

Silver, however, moved higher, with MCX silver March futures rising 0.50 per cent to Rs 1,82,705 per kg.

The focus in global markets is now on the Federal Reserve, which will announce its policy decision on Wednesday (December 10).The meeting comes at a time when the US job market is showing signs of cooling, even as inflation remains above the central bank's 2 per cent target.

Recent data showed that the Personal Consumption Expenditures (PCE) price index, the Fed's preferred inflation measure, rose 0.3 per cent in September, matching the increase in August.

On an annual basis, the index climbed 2.8 per cent, slightly higher than the 2.7 per cent rise seen in the previous month.

Meanwhile, US private payroll data released last week indicated the sharpest decline in more than two and a half years, with private sector jobs falling by 32,000 in November.At the same time, unemployment benefit claims dropped to 1,91,000 in the week ending November 29, the lowest level in more than three years and well below economists' expectations of 2,20,000.

Economists at Comerica expect the Federal Open Market Committee to reduce the federal funds rate by 25 basis points, bringing it to a range between 3.50 per cent and 3.75 per cent in its final policy move of the year.Although expectations of a rate cut generally support gold prices, the gains are being limited by higher bond yields.The benchmark US 10-year Treasury yield climbed to a two-and-a-half-month high on Monday, adding pressure on the precious metal.

Are new ITR forms coming before Fy28 Here's what the government says

New Delhi.(Agency)

The government will roll out new Income Tax Return (ITR) forms under the Income Tax Act, 2025 before the 2027–28 financial year begins. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary shared this update in the Lok Sabha on Monday.

NEW INCOME TAX ACT TO BEGIN FROM APRIL 2026

The new Income Tax Act was passed on August 21, 2025 and will officially come into effect from April 1, 2026. Once it begins, it will replace the six-decade-old Income Tax Act of 1961.The new law aims to simplify complicated clauses, cut down on unnecessary wordage, and make tax compliance smoother for individuals and businesses.

ITR FORMS BEING REDESIGNED FOR THE NEW SYSTEM

Chaudhary said that a CBDT committee is currently working on simplifying the ITR forms. The committee is consulting tax experts, industry bodies, and field officers to redesign the forms in a clearer and more user-friendly format.Under the new law, all forms, including quarterly TDS returns and annual income tax returns, are being updated to match the revised tax framework.

ITR FORMS FOR FIRST YEAR OF NEW REGIME COMING SOON

The ITR forms for the first tax year under the new Act, 2026–27, will include changes announced in the 2026 Budget. These forms will be notified before FY28 begins.

ICICI Prudential AMC IPO: Big brand, mega issue; but GMP slipping

Kolkata.(Agency)

Grey Market Premium, or GMP, of a public issue is an unofficial indicator, is extremely volatile and cannot guarantee anything, gain (or loss) on listing. Yet investors set great store by it and analysts often interpret it as a marker of the level of enthusiasm of investors in a public issue. The ICICI Prudential AMC IPO is set to flag off its bidding process on Dec 10. But despite the importance of the AMC in the mutual funds market, there has been a sharp drop in the GMP of the issue over the past few days. ICICI Pru is one of the most significant public issues in the market in 2025, which is being labelled as the year of IPOs.There is no clear explanation so far on why the GMP has dropped so dramatically. But there could be a few pointers. The recent volatility in the secondary markets could be impacting investor sentiment negatively. Also the issue comprises only OFS or Offer for Sale shares. A total of 4.9 crore shares will be sold by Prudential Corp Holding. The IPO will open on December 12 and close on December 16. The proceeds of OFS shares go the existing shareholders who offload their stake and the money doesn't accrue to the company. Also a low GMP itself offers a negative rub off on common investors -- they often construe it as a market of the investor sentiment around an issue.

ICICI Prudential AMC IPO price band

The ICICI Prudential AMC IPO price band has been fixed at Rs 2,061-2,165 per share. The anchor investment round will take place on Dec 11. The basis of allotment will be decided on Dec 17 and listing will take place on Dec 19.To manage this mega issue, ICICI Pru AMC has appointed a battery of lead managers -- Citigroup, Morgan Stanley, BofA, Axis Securities, CLSA, IIFL Capital, Kotak Mahindra Capital, SBI Caps, ICICI Bank, Goldman Sachs, Avendus, BNP Paribas, HDFC Bank, JM Financial, Motilal Oswal, Nuvama and UBS.

ICICI Pru business

ICICI Prudential AMC is a giant in the domestic MF industry and is the country's second-largest asset manager. This ranking takes into consideration quarterly average assets under management and ICICI Pru AMC is found to command 13.2% market share. It posted a PAT of Rs 1,618 crore and revenue of Rs 2,949.4 crore for the H1FY26 period.

Paramount's bid for Warner Bros: Trump says Netflix, Paramount are no friend of his

New Delhi.(Agency)

As the corporate thriller intensified around the $108-billion hostile bid from Paramount to take over Warner Bros and as the array of banks, billionaires and sovereign-wealth funds around the deal swelled, US President Donald Trump remarked that neither Netflix nor Paramount Skydance are great friends of his. It was clearly an effort to distance himself from both the raider and the target.Significantly, the stage is set for a riveting thriller with the dramatis following personae lined up -- the US president's son-in-law, a very large alternative-asset manager and (Larry Ellison) the CEO's father who once could boast of a fortune similar to that of Elon Musk. Reports indicated that the parties seemed to be coming together for spoiling Netflix Inc.'s deal last week.

Paramount CEO's assurance on funds

Reports said that Paramount CEO David Ellison (son of Larry Ellison) said in a letter to the Warner Bros board that the financing partners his firm would assure of the certainty to conclude the deal successfully. "We are providing you with funds certain from one of the wealthiest families in the world, a domestic counterparty, while also eliminating any cross-conditionality, which should give WBD's board complete comfort and certainty as to our ability to close in a timely fashion," he wrote in the letter.

The level of spice rises with the information that the Paramount CEO's father Larry Ellison, 81, and a founder of Oracle Corp, is a friend of Donald Trump and was also labelled by Bloomberg Billionaires Index as the world's richest person in September this year, when his wealth jumped by $89 billion in a day.

Delhi government notifies occupational safety draft rules, mandates advisory board

The labour department has invited suggestions and objections on the draft rules, which will be considered by the government after 45 days.

NEW DELHI.(Agency)

The Delhi government has notified draft Delhi Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2025, to ensure a safe working environment for workers employed in hazardous and accident-prone industrial activities.

The draft rules provide for the constitution of a 10-member Delhi Occupational Safety and Health Advisory Board headed by the labour commissioner, and safety committees in establishments employing 250 or more workers.

The labour department has invited suggestions and objections on the draft rules, which will be considered by the government after 45 days.

The draft rules state that every employer of a factory and building or other construction work will annually conduct, free of cost, medical examination of every worker aged 45 years and above, within 120 days from the commencement of every calendar year.

Every employer in the industry involving hazardous processes will arrange to conduct free-of-cost medical examinations for every worker annually, within 30 days from the commencement of every calendar year, as mentioned in the draft rules.

Additionally, no employee will be employed in any establishment unless he has been issued a letter of appointment. Under sub-section (1), Section 10 and Section 11 of the draft rules, the employer or manager of an establishment will, as early as possible, send a notice to the labour department inspector cum facilitators, about the occurrence of any accident that results in the death of a worker or results in bodily injury likely to cause death.

The dangerous occurrence will include the bursting of any plant or pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air; collapse or failure of a crane, derrick, winch, hoist or other appliances, explosion due to explosives, fire, leakage or release of harmful toxic gases and such other incident.

Under sub-section (2) of section 17 of the draft Rules, the Delhi government will constitute the "Delhi Occupational Safety and Health Advisory Board". The board members will include the chief inspector-cum-facilitator, labour department, member secretary, Delhi pollution control committee, director, Delhi health services, two representatives of employees and two members of the district crisis group having expertise in occupational safety and health.

Establishments involving hazardous processes and employing 250 or more workers will mandatorily form safety committees. The draft Delhi Occupational Safety, Health and Working Conditions Rules, 2025, was notified earlier this month. The draft rules also lay down working conditions stipulating daily and weekly working hours, wages and overtime payments.

New Rulebook for Safer Workplaces

- 10-member Advisory Board to be set up, headed by Labour Commissioner
- Safety committees mandatory for establishments with 250+ workers in hazardous sectors
- Appointment letter compulsory for every employee
- Weekly working hours capped at 48 hours

At 291, Delhi's air quality improves to 'poor' category

New Delhi.(Agency)

Delhi's air quality improved slightly on Tuesday, with the city recording an overall Air Quality Index (AQI) of 291 in the "poor" category at 9 am, according to the Central Pollution Control Board.

The city's AQI on Monday morning stood at 318 in the "very poor" category, the CPCB data showed.

Of the 38 monitoring stations across Delhi, 18 reported air quality in the 'very poor' category (AQI above 300), while 20 recorded 'poor' air quality (AQI above 200), as per data on the CPCB's Sameer app. According to CPCB, an AQI between 0 and 50 is classified "good", 51 to 100 "satisfactory", 101 to 200 "moderate", 201 to 300 "poor", 301 to 400 "very poor" and 401 to 500 "severe". On the weather front, the minimum temperature settled at 9.2 degrees Celsius, 0.4 notches below normal, while the morning relative humidity touched 100 per cent.

The India Meteorological Department (IMD) has forecast fog for the day. The maximum temperature is expected to reach around 22 to 24 degrees Celsius later in the day.

Delhi education department rolls out Winter plan for schools

The directorate of education (DoE) has emphasised that younger students are vulnerable to cold-related illnesses, making it imperative that schools ensure safe and conducive learning environments.

New Delhi.(Agency)

With the capital bracing for an intense winter marked by cold waves, dense fog and biting winds, the Delhi education department has rolled out a Winter Readiness Plan for all schools from ensuring hot meals and lukewarm drinking water to fixing broken doors, shifting assemblies indoors, monitoring students' clothing, and even providing heaters for security guards.

The comprehensive directive, issued on December 8, pushes all government, government-aided and private unaided recognised schools to take proactive, child-centric measures as the capital prepares for a prolonged cold spell.

The directorate of education (DoE) has emphasised that younger students are vulnerable to cold-related illnesses, making it imperative that schools ensure safe and conducive learning environments. One of the core measures outlined in the circular is the strengthening of the mid-day meal (MDM) programme. Schools must serve hot, freshly prepared and nutritious meals on time to ensure they reach children while still warm. They must also arrange adequate indoor seating so students do not have to eat in the cold.

To help students better cope with freezing temperatures, schools have been advised to provide lukewarm drinking water using kettles, insulated jugs or heating equipment, with SMC funds available for government schools to facilitate this. Regular cleaning of water containers and prioritising younger children for warm water access have been highlighted as essential steps. Class teachers are required to conduct daily checks to ensure students arrive in proper winter clothing, helping identify children who may need support.

DMRC partners with IIT-Hyderabad to strengthen last-mile connectivity

The partnership, formalised on Monday, seeks to leverage the technical expertise and innovation capabilities of both organisations in the field of autonomous navigation.

New Delhi.(Agency)

The Delhi Metro Rail Corporation has signed a MoU with IIT-Hyderabad's Technology Innovation Hub for Autonomous Navigation (TiHAN) to advance next-generation mobility solutions aimed at strengthening last-mile connectivity and public transport networks.

The partnership, formalised on Monday, seeks to leverage the technical expertise and innovation capabilities of both organisations in the field of autonomous navigation.

Officials said the collaboration will focus on developing safe, smart and scalable mobility systems that can support driverless ground vehicles, robots, drones and other autonomous platforms designed to operate without human intervention.

TiHAN, established under the Department of Science and Technology's National Mission on Cyber Physical Systems, specialises in creating autonomous navigation and data acquisition systems. These technologies enable unmanned platforms to navigate complex environments, collect real-time data and enhance transportation efficiency. DMRC officials said such advancements could significantly improve last-mile connectivity for metro commuters.

The MoU was signed by Shobhan Chaudhuri, Advisor (R&D) at DMRC, and Dr. Santosh Reddy, Hub Executive Officer at TiHAN, in the presence of DMRC Managing Director Dr. Vikas Kumar, Director (Infrastructure) Manuj Singhal and other senior DMRC officials. From IIT Hyderabad, Dean (Innovation) Prof. Malla Reddy and Prof. P. Rajalakshmi were also present.

ED move against former minister gives hope: Delhi BJP president Virendra Sachdeva

The case pertains to alleged irregularities in the upgradation of 10 sewage treatment plants in the capital during the tenure of the Arvind Kejriwal government.

New Delhi.(Agency)

Delhi BJP president Virendra Sachdeva on Monday welcomed the Enforcement Directorate's chargesheet against former Delhi water minister Satyendar Jain and former Delhi Jal Board CEO Udit Prakash Rai in the alleged Rs 17.70-crore sewage treatment plants tender scam. The case pertains to alleged irregularities in the upgradation of 10 sewage treatment plants in the capital during the tenure of the Arvind Kejriwal government.

Sachdeva said the filing of the chargesheet has renewed hope that those involved in the scam "under the Kejriwal government" will soon face punishment. He added that the case appears strong as the ED has already attached assets worth Rs 15.36 crore belonging to Jain and other accused, and the agency has duly informed the court about the attachments.

Delhi Court extends NIA custody of four accused in Red Fort blast case

This is the latest development in the NIA's ongoing probe into what investigators have described as a "white-collar" terror module, originally exposed by the Jammu and Kashmir Police.

New Delhi.(Agency)

A Delhi court on Monday extended the National Investigation Agency (NIA) custody of four accused in the November 10 Red Fort blast case by four more days. The accused doctors Muzammil Ganai, Adeel Rather, Shaheena Saeed and preacher Irfan Ahmed Wagay were produced before Principal and Sessions Judge Anju Bajaj Chandna on the expiry of their initial 10-day custody granted on November 29.

The hearing took place amid tight security in and around the Patiala House Courts, with mediapersons barred from entering the courtroom.

This is the latest development in the NIA's ongoing probe into what investigators have described as a "white-collar" terror module, originally exposed by the Jammu and Kashmir Police. The explosion outside the Red Fort on November 10 killed 15 people and left several others injured.

Goa trip of family hailing from Delhi ends in 'loss beyond comprehension', last rites held

But what began as a joyful trip turned into a nightmare when a devastating fire broke out at a nightclub, killing four members of the group.

New Delhi.(Agency)

Bhavna Joshi, her husband, and her three sisters left Delhi on December 4 for a long-awaited holiday to Goa. But what began as a joyful trip turned into a nightmare when a devastating fire broke out at a nightclub, killing four members of the group. Bhavna emerged as the sole survivor, left to cope with the unimaginable loss.

A pall of gloom descended in northeast Delhi's Karawal Nagar, when their bodies arrived at their home on Monday afternoon. The atmosphere was filled with mourning as coffins reached around 2.30 pm. After the postmortem examination, the bodies were flown to Delhi, and the last rites were performed at Nigambodh Ghat.

Bhavna's husband, Vinod, and her sisters Saroj, Anita, and Kamla were among the 25 people who died when a fire engulfed the nightclub in North Goa's Arpora on Saturday night. Bhavna survived with injuries, police said.

The group had planned the trip for months, repeatedly postponing it due to various obstacles. They finally managed to travel on December 4 and were scheduled to return on December 9. Vinod had joined them to ensure they felt safe throughout the journey. When the fire broke out, all five were present.

As chaos spread, Vinod pushed Bhavna out through the main gate to save her, then rushed back inside to rescue Kamla, Saroj and Anita, but got trapped. Deepak, a relative, said Vinod's family—originally from Almora in Uttarakhand—included his elderly mother, Bhavna, their five-year-old daughter, and 11-year-old son.

Kamla and Bhavna were real sisters married into the same household. Anita had married Vivek Joshi of Lucknow on December 11, 2024. Saroj, who worked in the travel industry, was unmarried and lived with her father in Rohini Sector 23.

The family received the news around 10 am on Sunday. Naveen, Vinod's elder brother, flew to Goa, where Bhavna was found in a semi-conscious state. He identified the bodies of his brother, his wife, and his two sisters-in-law.

Except for Vinod's coffin, none of the others were opened. All bodies were taken directly to the crematorium.The victims' father was inconsolable. Anita's husband, Vivek, whose first anniversary is in three days, said he still could not believe she was gone.

NEWS BOX

Chinese court orders Malaysia Airlines to pay compensation over missing flight Mh370

BEIJING. (Agency)

A Beijing court has ruled that Malaysia Airlines must pay 2.9 million yuan ($410,000) each to the families of eight passengers who went missing in the mysterious disappearance of the MH370 flight more than a decade ago.The court ordered the airline to pay each family compensation for the death of their loved one, funeral expenses, and damages stemming from emotional distress, it said in a statement Monday. Although it is not known what happened to the passengers, they have been declared legally dead.There were 239 passengers and crew members on the flight that disappeared after departing Kuala Lumpur for Beijing in 2014.

Despite years of searches, it's unknown why the plane went down or what happened to the people on board. Most of the passengers were Chinese, and their families in China have continued to seek answers.

The court said that another 23 cases remain pending. In 47 other cases, families have reached agreements with the airlines and withdrawn their suits.Last Wednesday, the Malaysian government said it would resume a search for the missing plane starting Dec. 30.

'Why India dumping rice into US': Trump's new tariff threat amid US trade talks

world. (Agency)

US President Donald Trump said India should not be "dumping" rice into the U.S. market and said he will "take care" of the issue, emphasising that tariffs would easily solve the "problem."This comes amid United States Under Secretary of State for Political Affairs Allison Hooker's visit to New Delhi and Bengaluru from December 7 to 11.

The visit is expected to sharpen the strategic focus of the US-India partnership at a time when both sides are navigating economic friction, geopolitical volatility and rapid technological shifts. According to the US Embassy, Hooker will prioritise advancing the US-India strategic partnership, deepening economic and commercial ties, expanding American exports, and accelerating collaboration in emerging technologies, particularly artificial intelligence and space exploration.Her visit comes amid renewed efforts in Washington and New Delhi to stabilise ties after weeks of heightened tensions over the Trump administration's 50% tariff on Indian goods and India's continued purchase of Russian energy.

On Monday, Trump hosted a White House roundtable with farming and agriculture representatives, joined by key cabinet members including Treasury Secretary Scott Bessent and Agriculture Secretary Brooke Rollins.

He announced USD 12 billion in federal aid for farmers.Meryl Kennedy, who runs her family's agribusiness, Kennedy Rice Mill in Louisiana, told Trump that rice producers in the southern United States are "really struggling" and that other countries are "dumping" rice into the U.S. market.When asked by Trump which countries are dumping rice into America, Kennedy, sitting next to the President, replied, "India, and Thailand; even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for US rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years."

2 Afghan Teens Jailed For Raping 15-Year-Old Girl In England

world. (Agency)

Two teenage Afghan asylum seekers, who had both arrived in Britain alone in the last year, were given long detention sentences on Monday for raping a 15-year-old girl in central England.

The boys, Jan Jahanzeb and Israr Niazal, both aged 17, carried out the attack in a park in Leamington Spa in May after taking the girl, who was very drunk at the time, away from her friends, prosecutors told Warwick Crown Court.The court was played footage that the highly distressed girl had managed to capture during the attack, in which she could be heard sobbing loudly and screaming: "Please help me ... let me go ... I want to go home.""The day I was raped changed me as a person," the girl, who said the incident was her first sexual experience, said in a victim statement.

MAJOR POLITICAL ISSUE

Crimes, particularly sexual offences, committed by asylum seekers have become a major political issue in Britain, especially as the government is seeking a solution to stop thousands of migrants arriving in small boats from across the Channel.Last month, an Afghan national pleaded guilty to raping a 12-year-old girl in Nuneaton, in central England, while an Ethiopian man was jailed in September after being convicted of sexually assaulting a teenage girl and another woman in Epping, north of London.

Both cases sparked large-scale protests, some of which turned violent, and prompted demonstrations across the country at hotels housing asylum seekers. Immigration concerns have also helped to propel the populist Reform UK party to lead in opinion polls.

In an acknowledgment of the public concern, the judge Sylvia de Bertodano ordered that the two teenagers, who pleaded guilty in October, could be named despite being only 17, saying it was in the public interest to do so.Jahanzeb, who turns 18 at the start of next year, was given detention of 10 years and eight months, while Niazal was sentenced to nine years and 10 months in detention. Jahanzeb's lawyer Robert Holt said his client had travelled through Europe alone to get to Britain in January, succeeding on his fourth attempt to cross the Channel on a small boat. He faces automatic deportation after his sentence is completed.

Protesting Greek farmers swarm onto airport tarmac in Crete, forcing halt to flights

The clashes in Crete are the latest escalation in farmer protests over delays in the payment of European Union-backed agricultural subsidies in the wake of a scandal which revealed fraudulent subsidy claims.

DOUANKARA. (Agency)

ATHENS: Angry farmers protesting delays in the payment of subsidies swarmed onto the aircraft parking area of the international airport on the southern Greek island of Crete on Monday, managing to evade riot police who used tear gas and stun grenades to keep them backImages from local media showed dozens of farmers standing on a section of the tarmac at the Nikos Kazantzakis international airport in Heraklion, the main town in Crete, forcing the airport to suspend all flights.Clashes also broke out near the airport of Crete's second-largest city, Chania, with riot police using tear gas to disperse protesting farmers who pelted them with rocks and overturned a police patrol car, local media reported. Two people were reportedly injured in ChaniaThe clashes in Crete are the latest escalation in farmer protests over delays in the payment of European Union-backed agricultural subsidies in the wake of a scandal which revealed fraudulent subsidy claims.Farmers have deployed thousands of tractors and other agricultural vehicles at border crossings and key points along highways across the country, periodically stopping traffic and threatening to completely blockade roads, as well as ports and airports.On Friday, riot police fired tear gas at protesting farmers attempting to

block the main access road to the international airport outside the northern Greek city of Thessaloniki.Police have been enforcing traffic diversions in several parts of northern and central Greece to skirt the blockades, while farmer roadblocks at the country's northern borders with Bulgaria, Turkey and North Macedonia have already hampered truck traffic, causing long backup lines of freight vehicles.The payment delays have come as authorities review all requests following revelations of widespread fraudulent claims for EU farm subsidies. Protesters have argued that the delays amount to collective punishment, leaving honest farmers in debt and unable to plant their fields for next season.Greece's farming sector has also been hit this year by an outbreak of goat and sheep pox that led to a mass cull of livestock.Michalis Chrisochoidis, the minister for public order, said last week that the government remained open to talks with protest leaders, but warned that it wouldn't tolerate the shutdown of major transit points.Protests by farmers are common in Greece, and similar blockades in the past have sometimes severed all road traffic between the north and south of the country for weeks.The subsidy scandal prompted the resignation of five senior government officials in June, and the phased shutdown of a state agency that handled agricultural subsidies. Dozens of people have been arrested for allegedly filing false claims, in response to an investigation led by the European Public Prosecutor's Office.

Civilian deaths mount as Cambodia–Thailand border fighting escalates

world . (Agency)

Cambodia has retaliated in a reignited border conflict with Thailand, the former leader of Cambodia said Tuesday, after Phnom Penh accused Thai forces of shelling positions overnight in fighting that has killed seven civilians and a Thai soldier.

The Thai military fired shells into the border province of Banteay Meanchey after midnight, killing two people travelling on National Road 56, the Cambodian defence ministry said in a Facebook post.Ministry spokeswoman Maly Socheata later told reporters that seven civilians had been killed and 20 wounded in Thai attacks as of Tuesday morning.The ministry said in a separate statement that the Thai army had resumed attacks around 5:00 am Tuesday in border regions, including in the area of centuries-old temples, such as the UNESCO world heritage site, the Preah Vihear temple.Five days of combat in July between the two Southeast Asian nations killed dozens of people and displaced around 300,000 on both sides of the border before a truce took effect.

The two countries have blamed each other for the renewed fighting, which saw Thailand launch air strikes and use tanks against its neighbour on Monday.

Cambodia's influential former leader

Hun Sen said Tuesday his country had retaliated against Thailand, after Phnom Penh denied firing back for two days."After being patient for more than 24 hours in order to respect the ceasefire and for time to evacuate people to safety, yesterday evening we retaliated with more (responses) last night and this morning," the Senate president and former prime minister said in a Facebook post."Now we fight in order to defend ourselves again," he added.Tens of thousands of people have evacuated from border regions since the fresh fighting began on Sunday, officials have said.In Thailand's Surin province, Sutida Pusa, 30, who runs a small food shop, told AFP on Monday that her young and elderly relatives were moved to an evacuation centre the day before, while others stayed behind to guard their property.She has travelled back and forth between the temporary shelter and her house -- located less than 20 kilometres (12 miles) from the border -- to care for family members in both places."I wanted to see the situation first, as the sounds of fighting aren't as loud as during the major clash on July 24," she said.

"We never trust the situation."

Cambodian information minister Neth Pheaktra told AFP that at least four civilians were killed by Thai shelling on Monday in two border provinces.

Around 10 other civilians were wounded, he said on Monday.The Thai army has said one soldier was killed and 18 others were wounded since Sunday.

It said Tuesday that Cambodian artillery shells had fallen on two civilian homes in Sa Kaeo province, with no casualties reported.

Netanyahu defends leadership during Gaza war, touts his strong connect with world leaders, including PM Modi

BANGKOK. (Agency)

JERUSALEM: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, in a fiery speech at the Knesset (Israeli parliament) on Monday (December 8, 2025), defended his handling of the country's affairs, asserting that despite a wave of anti-semitism against the Jewish state, it enjoys an unprecedented support from many countries and leaders, including Prime Minister Narendra Modi.Speaking during a so-called '40-signature debate', a parliamentary mechanism that allows the Opposition to compel the Prime Minister to appear once a month at the Knesset forum, Netanyahu put up a strong defence of his government's policy on various fronts, including Israel's foreign relations. "Israel is today stronger than ever," he said.

The Israeli Premier hit back at what the Opposition described as "the collapse of Israel's international standing," arguing that Israel remained diplomatically, militarily, and economically dominant despite its two years at war with Hamas, highlighting his ties to global leaders.Sitting through a series of scathing criticisms from opposition members, Netanyahu opened his speech by mocking the subject of the debate, calling the assertion that Israel's global standing has collapsed over the war "a detachment from reality," and insisting that "Israel today is stronger than ever." "It is the strongest power in the Middle East, and in certain fields, it is a global power," Netanyahu stressed, claiming that "this is a direct result of the way we have led the War of Revival".The Israeli government decided to name the war that started with the attack of Hamas on its territory on October 7, 2023, as the 'War of Revival' in October, a decision that many in Israel contest."Many states around the world and very many world leaders are seeking us out," Netanyahu said before acknowledging that "there are challenges" as well.He blamed the "waves of antisemitism" sweeping the West as a result of two things: radical Muslim minorities that have entered almost every country, first and foremost in Europe, and antisemitic incitement on social media, "incitement amplified by anti-Zionist governments and organisations".“We are fighting this antisemitism around the world," he continued, noting that his government has made an unprecedented allocation of some NIS 2.35 billion ($725 million) to the Foreign Ministry "to combat this propaganda".“I believe we must fight it with new methods," Netanyahu said, while insisting that "we must look at our tremendous achievements".Despite this, Netanyahu argued tat Israel's diplomatic standing remained significant, pointing to the visit of German Chancellor Friedrich Merz this week, a visit he said came at Merz's request.

Federal judge throws out Trump order blocking development of wind energy

WASHINGTON .(Agency)

A federal judge on Monday struck down President Donald Trump's executive order blocking wind energy projects, saying the effort to halt virtually all leasing of wind farms on federal lands and waters was "arbitrary and capricious" and violates U.S. law.Judge Patti Saris of the U.S. District Court for the District of Massachusetts vacated Trump's Jan. 20 executive order blocking wind energy projects and declared it unlawful.Saris ruled in favor of a coalition of state attorneys general from 17 states and Washington, D.C., led by New York Attorney General Letitia James, that challenged Trump's Day One order that paused leasing and permitting for wind energy projects.Trump has been hostile to renewable energy, particularly offshore wind, and prioritizes fossil fuels to produce electricity.Massachusetts Attorney General Andrea Joy Campbell hailed the ruling as a victory for green jobs and renewable energy."Massachusetts has invested hundreds of millions of dollars into offshore wind, and today, we successfully protected those important investments from the Trump administration's unlawful order," Campbell said in a statement.James said she was grateful the court stepped in "to block the administration's reckless and unlawful crusade against clean energy."“As New Yorkers face rising energy costs, we need more energy sources, not fewer," James said. "Wind energy is good for our environment, our economy, and our communities."The coalition that opposed Trump's order argued that Trump doesn't have the authority to halt project permitting, and that doing so jeopardizes the states' economies, energy mix, public health and climate goals.The coalition includes Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Rhode Island, Washington state and Washington, D.C. They say they've invested hundreds of millions of dollars collectively to develop wind energy and even more on upgrading transmission lines to bring wind energy to the electrical grid.

Japan assesses damage from 7.5 magnitude quake that injured 33

TOKYO. (Agency)

Japan was assessing damage Tuesday and cautioning people of potential aftershocks after a late-night 7.5 magnitude earthquake caused injuries, light damage and a tsunami in Pacific coastal communities.At least 33 people were injured, one seriously, the Fire and Disaster Management Agency said. Most of them were hit by falling objects, public broadcaster NHK reported.Prime Minister Sanae Takaichi told reporters an emergency task force was formed to urgently assess damage. "We are putting people's lives first and doing everything we can," she said.At a parliamentary session Tuesday, Takaichi pledged the government would continue its utmost effort and reminded people they have to protect their own lives.The 7.5 magnitude quake struck around 11:15 p.m. in the Pacific Ocean, around 80 kilometers (50 miles) off the coast of Aomori, the northernmost prefecture of Japan's main Honshu island.The U.S. Geological Survey measured the quake at 7.6 magnitude and said it occurred 44 kilometers (27 miles) below the surface.

A tsunami of up to 70 centimeters (2 feet, 4 inches) was measured in Kuji port in Iwate prefecture, just south of Aomori, and waves up to 50 centimeters struck other communities in the region, the Japan Meteorological Agency said. NHK reported the waves damaged some oyster rafts.The agency lifted all tsunami advisories by 6:30 a.m. Tuesday.

Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara said about 800 homes were without electricity and Shinkansen bullet trains and some local lines were suspended in parts of the region in the early hours of Tuesday. East Japan Railway said it is aiming to resume bullet trains in the region later Tuesday.

Power was mostly restored by Tuesday morning, according to the Tohoku Electric Power Co.About 480 residets sheltered at Hachinohe Air Base and 18 defense helicopters were mobilized for a damage assessment, Defense Minister Shinjiro Koizumi said.About 200 passengers were stranded for the night at New Chitose Airport in Hokkaido, NHK reported. Part

of a domestic terminal building was unusable Tuesday after parts of its ceiling cracked and fell to the floor, according to the airport operator.The Nuclear Regulation Authority said about 450 liters (118 gallons) of water spilled from a spent fuel cooling area at the Rokkasho fuel reprocessing plant in Aomori, but that its water level remained within the normal range and there was no safety concern. No abnormalities were found at other nuclear power plants and spent fuel storage facilities, the NRA said.JMA cautioned about possible aftershocks in the coming days. It said there is a slight increase in risk of a magnitude 8-level quake and possible tsunami occurring along Japan's northeastern coast from Chiba, just east of Tokyo, to Hokkaido. The agency urged residents in 182 municipalities in the area to monitor their emergency preparedness in the coming week, reminding them that the caution is not a prediction of a big one.Monday's quake occurred just north of the coastal region where the magnitude 9.0 quake and tsunami in 2011 killed nearly 20,000 people and destroyed the Fukushima Daiichi nuclear power plant.

"You need to prepare, assuming that a disaster like that could happen again," JMA official Satoshi Harada said.Smaller aftershocks were continuing Tuesday.

NEWS BOX

Rohit Sharma helped me feel comfortable, play freely in early career: Shardul Thakur

Mumbai. (Agency)

India all-rounder Shardul Thakur's return to Mumbai Indians has brought a sense of familiarity and renewed purpose, and the all-rounder credits Rohit Sharma for shaping that comfort early in his career. Traded from Lucknow Super Giants for Rs 2 crore ahead of IPL 2026, Thakur believes reuniting with Rohit will help him rediscover the freedom and clarity that defined his formative years in competitive cricket.

Speaking on the Mumbai Indians website, Thakur said Rohit played a defining role in allowing him to express himself during the early stages of his journey. The fast bowler also shared that their bond grew naturally, giving him the confidence to perform without fear or hesitation."He (Rohit Sharma) made me comfortable, he allowed me to be free

with him, he allowed me to express myself. We became comfortable with each other and he played a major part in it," Shardul said."I was lucky enough to experience the dressing room early in my days. I was already feeling comfortable in front of senior players. Somewhere down the line, whatever the way I was treated during Mumbai Indians camp also, that small gesture from the Mumbai Indians helped me a lot to grow in my career," he added.His association with MI dates back to 2010, when he joined as a young support bowler. Thakur said that early exposure to a championship-level environment helped him grow rapidly. He bowled in practice games, interacted with senior players, and gained invaluable confidence.

"I was already feeling comfortable in front of senior players. That small gesture from Mumbai Indians helped me a lot to grow," he said.Thakur credits coaches Rahul Sanghvi and Paras Mhambrey for mentoring him daily, while sharing space with icons like Sachin Tendulkar, Harbhajan Singh, Andrew Symonds, Munaf Patel and Rohit Sharma left a lasting impact. The memory of peeking into Wankhede Stadium from a passing train to catch a glimpse of Tendulkar remains one of his most nostalgic stories.

Hardik, Axar on cusp of historic landmarks as India eye T20I series win vs South Africa

India and South Africa are set to clash in a five-match T20I series, starting December 9 in Cuttack. After losing the Test series, India bounced back to win the ODI series and will now aim to carry that momentum into the T20Is.

New Delhi. (Agency)

India enter the T20I series against South Africa following a mixed home campaign. After losing the preceding Test series 2–0, they bounced back to claim the ODI series 2–1. In the decisive third ODI at Visakhapatnam, opener Yashasvi Jaiswal scored an unbeaten 116, while Virat Kohli contributed a lively 65, guiding India to a comfortable nine-wicket victory.The ODI win was significant not only for the result but also for restoring confidence and composure. India's bowlers, particularly Kuldeep Yadav and Prasidh Krishna, performed under pressure, restricting South Africa to 270.India now head into the T20I series with strong momentum, having remained unbeaten in bilateral T20I series since a 2–3 loss to the West Indies in August 2023, winning nine series and drawing one since then.Despite recent setbacks in Tests, the white-ball team appears rejuvenated. With a balanced squad, renewed confidence, and the backing of the home crowd, India will be keen to carry this momentum into the T20Is and reinforce their dominance in the shortest format.246 - Runs Suryakumar Yadav needs to become the third Indian batter in Men's T20Is after Rohit Sharma and Virat Kohli to complete 3000 runs.Runs Suryakumar Yadav needs to complete 9000 runs in T20s. Virat Kohli, Rohit Sharma and Shikhar Dhawan are the other Indians to have achieved the feat.

6 - Sixes Suryakumar Yadav needs to complete 400 sixes in T20s. Amongst Indians, only Virat Kohli and Rohit Sharma have achieved the feat.163 - Runs Shubman Gill needs to complete 1000 runs in T20Is.

4 - Runs Tilak Verma needs to complete 1000 T20Is runs. He can also become the fourth-fastest to the milestone with Virat Kohli on top followed by Abhishek Sharma, KL Rahul and Suryakumar Yadav.

2 - Wickets Hardik Pandya needs to complete 100 wickets in T20Is. Arshdeep Singh is the only Indian to have reached the landmark in Men's T20Is.2 wickets, 140 runs - If Hardik Pandya scores 140 runs and picks up 2 wickets, he will be the first Indian and fourth overall to achieve the landmark of 2000 runs and 100 wickets in Men's T20Is. The others are Shakib Al Hasan, Mohammad Nabi, Virandeep Singh and Sikandar Raza.47 - Runs Axar Patel needs to become the first Indian to score 3500 runs and take 250-plus wickets in Men's T20s.5 - Runs Sanju Samson needs to complete 1000 runs in Men's T20s Runs Sanju Samson needs to become the sixth Indian to score 8000 runs in Men's T20s. The others are Virat Kohli, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Suryakumar Yadav and KL Rahul.

Josh Hazlewood ruled out of Ashes, Pat Cummins set to return for Adelaide Test

New Delhi. (Agency)

Australia fast bowler Josh Hazlewood has been ruled out of the entire Ashes series due to an Achilles issue. The right-arm seamer hurt his hamstring while featuring in Australia's domestic Sheffield Shield competition and subsequently missed the first two Tests.He was scheduled to join the Australian squad in Brisbane to continue his recovery, but unfortunately developed Achilles soreness during his rehabilitation, which has resulted in him being ruled out of the entire rubber.Australia head coach Andrew McDonald informed the media about Hazlewood's injury and revealed that his focus is now to be fully fit for the T20 World Cup 2026 in India."Unfortunately, Josh won't be a part of the Ashes. Really, really flat for him. A couple of setbacks that we didn't see coming, and we thought he would play a huge part in the series. It's a totally separate injury. It's somewhere lower in the calf to Achilles region. His preparation will then shift towards the World Cup, which is an incredibly important campaign for us," McDonald was quoted as saying by cricket.com.au.Meanwhile, in a major boost for Australia, captain Pat Cummins

will return for the third Test scheduled to be played in Adelaide from 17–21 December. McDonald revealed that Cummins underwent match simulations at the Allan Border Field and confirmed that he is ready to go for the third Test."There won't be any match opportunities for Pat (before Adelaide) – and this is something we've done with Pat before long-ish layoffs, where we've put some time and effort into rebuilding his body. He was out at Allan Border Field whilst everyone was at the Gabba; he simulated pretty much what a match will look like out there with multiple spells. His body's ready to go and, barring anything else happening in the next week, I'd be expecting Pat to be tossing the coin and putting the blazer on," McDonald added.Despite the absence of their two pace stalwarts, Australia registered comfortable wins in the first two Tests in Perth and Brisbane and are now leading the series 2–0. In Cummins' and Hazlewood's absence, Mitchell Starc took the responsibility on his shoulders and delivered back-to-back match-winning performances, claiming 18 wickets across the two matches, along with a brilliant knock of 77 in Brisbane. With Cummins set to return for the third Test, Australia's bowling attack will receive a major boost as they aim to take an unassailable 3–0 lead in the series.

IPL 2026 auction full list: Venkatesh Iyer and Steve Smith headline top prize bracket

CHRISTCHURCH. (Agency)

The Rs 2 crore bracket has become the focal point of the IPL 2026 auction, and it's easy to see why. Sitting at the top of the reserve-price pyramid are 40 players who believe they are worth every bit of the league's premium valuation. Among them, Cameron Green stands out as the one franchises are expected to chase hardest — a multi-dimensional all-rounder whose batting range and seam bowling make him the headline attraction, especially for big-purse teams like KKR and CSK.But the high-value drama doesn't end with Green. Venkatesh Iyer, once secured by KKR for a staggering Rs 23.75 crore, returns to the auction pool after an inconsistent 2025 season. His re-entry at the highest base price is one of the more intriguing subplots.Adding further character to this Rs 2 crore ensemble is Australia stalwart Steve Smith, who has made a surprise comeback to the auction list after being absent from the league since 2021. His decision to list himself at the top bracket hints at unfinished T20 ambitions and injects a nostalgic twist into this year's proceedings. Together, these names

contribute to a top tier that is more colourful, unpredictable and star-studded than usual.The BCCI's final shortlist consists of 350 players, trimmed down from 1,390 registrations — featuring 240 Indians, 110 overseas names, 224 uncapped Indian talents and 14 uncapped overseas entrants. With 77 slots available, including 31 for overseas players, December 16 in Abu Dhabi promises plenty of theatre, especially when these top-bracket names go under the hammer.

IND vs SA 1st T20I, Cuttack weather report: Will rain play spoilsport in series opener

New Delhi. (Agency)

Having won the ODI series, India will now take on South Africa in a five-match T20I series beginning on Tuesday, December 9, at Barabati Stadium in Cuttack. After being whitewashed in the Tests, the Men in Blue struck back by clinching the ODI leg and will now look to carry that momentum into the T20Is as well.The Suryakumar Yadav-led side is unbeaten in the format since their T20 World Cup 2024 triumph, having won every series since. With the next World Cup just two months away, the defending champions are focused on fine-tuning their preparations for the upcoming mega event.

As India build up to the T20 World Cup, there are growing speculations regarding the weather conditions ahead of the first T20I. While the afternoon forecast is bright and sunny, the evening is expected to be cloudy

during the match.There is a ten-percent chance of rain in the evening, which might cause some interruptions. With cloudy conditions expected and dew likely to settle in during the second half, the captain winning the toss may prefer to bowl first.The pitch at Barabati Stadium features a new red-soil base and is traditionally known to assist batting. Spinners often come into play during the middle overs, and teams batting second are expected to gain an advantage due to the presence of dew. All in all, it is set to be an excellent batting surface with plenty of runs on offer.Meanwhile, South Africa will be determined to bounce back after a disappointing ODI series. Led by their own explosive core of T20 specialists, the visitors will look to challenge India with an aggressive approach.

Has Mohamed Salah already played his last Liverpool game Arne Slot has no clue

Arne Slot's admission that he has "no clue" about Mohamed Salah's future deepened Liverpool's ongoing uncertainty. The fallout from Salah's interview has left the club navigating one of its most delicate moments of the season.

New Delhi. (Agency)

FLiverpool's uncertain season took another dramatic turn as head coach Arne Slot admitted he has "no clue" whether Mohamed Salah will feature for the club again. The Dutchman's comments came just days after Salah's explosive interview at Leeds, where the Egyptian forward suggested his relationship with the manager had deteriorated. The fallout has cast a shadow over Liverpool's preparations during a crucial period, with the forward now left out of the squad for the Champions League trip to Inter Milan.Speaking at his pre-match press conference on Monday, Slot said he was caught off guard by Salah's claims and

was surprised to hear the forward airing such frustration publicly. Slot confirmed that the only communication since the interview was informing Salah he would not travel to Italy, adding that he had never sensed a breakdown between them."I have no clue," Slot replied on whether Salah will be playing for Liverpool again. "I cannot answer that question at this point in time,"However, the manager also made it clear that Liverpool's decision to exclude Salah was deliberate. Slot said he remains calm and polite but "not weak," emphasising that the club needed to respond in its own way to Salah's remarks. He declined to speculate on who Salah meant when the forward said he had been "thrown under the bus," saying only the player could answer that.I haven't felt that at all until Saturday evening for sure. When I don't play someone usually players don't like the manager that much but he was really respectful to the staff and manager, his teammates and he trained very hard so it was a surprise to me when I heard the comments he gave. But it is not the first or last time a player who doesn't play says something similar to what he did. But my reaction to that is clear and that's why he is not here tonight," Slot said.

IPL 2026: 350 players finalised for auction, Quinton de Kock makes surprise entry

The BCCI has unveiled the full list of players finalised for the IPL 2026 auction scheduled to be held in Abu Dhabi on December 16. 240 Indians and 110 overseas players will go under the hammer during the bidding event.

New Delhi. (Agency)

A total of 350 players have been finalised for the Indian Premier League 2026 (IPL 2026 auction) as the BCCI unveiled the list on Tuesday, December 9. 1,390 players had originally showed their interest for the bidding event, scheduled to be held on December 16 in Abu Dhabi.

After the shortlisting process, the final pool has been trimmed to 350 players, comprising 240 Indian and 110 overseas recruits. The group includes 224 uncapped Indian players and 14 uncapped overseas players, ensuring a strong blend of experienced options and emerging talent.The ten franchises will have 77 available slots to fill during the auction, including 31 positions reserved for overseas players. With teams aiming to rebuild or strengthen ahead of the 2026 season, intense bidding battles are expected.The highest base price category remains at Rs 2 crore, with 40 players opting to enter the auction in this premium bracket. As always, big-name stars in this band are set to be among the most sought-after on auction day. Among Indians, only Venkatesh Iyer and Ravi Bishnoi have kept their base price at Rs 2 Crore.The auction proceedings will begin at 1:00 PM UAE time (2:30 PM IST) on Tuesday, December 16 as teams begin their preparations for another action packed season of the T20 extravaganza.

The final list includes 35 new names which were not part of the initial list and one surprise entry among them is Quinton de Kock. The wicketkeeper batter played for Kolkata Knight Riders (KKR) in the last season after being bought at the mega auction for Rs 2 Crore. However, he was released by the franchise after an underwhelming season, which saw him score just 152 runs from eight innings.Steve Smith,Josh Inglis in final list

Cameron Green, Matthew Short and Steve Smith headline the list of Australian players hoping to attract bids at the auction. Even Josh Inglis, whose availability remains uncertain due to his wedding, has surprised his former franchise by putting his name forward.The extensive roster also features England's Jamie Smith and Jonny Bairstow, New Zealand stars Rachin Ravindra, Daryl Mitchell and Devon Conway, as well as Sri Lankan talents Wanindu Hasaranga and Matheesha Pathirana, among several others.

Among all ten franchises, Kolkata Knight Riders will head to mini-auction with the largest purse of 64.30 crore, while Chennai Super Kings have the second largest amound with 43.40 crore at their disposal.

Kritika Kamra

Says It's A 'Privilege' To Be A Protagonist Written By A Woman' In The Great Shamsuddin Family

The much-awaited trailer of The Great Shamsuddin Family is finally out, and audiences are already buzzing about Kritika Kamra's presence in it that feels real and lived in. Slated to premiere on 12th December on Jio Hotstar, the film marks the return of Anusha Rizvi, the acclaimed filmmaker behind Peepli Live.The film features an impressive ensemble cast including Farida Jalal, Shreya Dhanwanthary, Juhi Babbar Soni and Sheeba Chadda, bringing together generations of stellar performers in a story rooted in emotion, humour and timely social relevance.

Kritika Kamra, who headlines the project, shared her excitement about the film and the journey of portraying a character crafted by a female filmmaker with a distinct voice.Kritika Kamra says "Being at the centre of a story written by a woman especially someone as sharp, thoughtful and fearless as Anusha is a privilege I deeply value. When I read the script of The Great Shamsuddin Family, I was instantly drawn to how authentic, layered and unapologetic her characters are. Women on screen are often boxed into stereotypes, but this story gives women the space to be flawed, funny, messy, vulnerable, assertive..everything at once."This film is also very special to me because it gave me the opportunity to work alongside an incredible team of women both behind and in front of the camera. Sharing screen space with legends like Farida ji and Dolly ji and perform with phenomenal actors like Sheeba ma'am, Juhi and Shreya has been a learning experience I will always cherish. I truly believe our film has warmth, joy and at the same time something deeply meaningful to say. I'm proud to be part of a narrative that celebrates complexity, womanhood and identity in such an honest way."Director Anusha Rizvi brings her signature grounding in realism, humour and social observation to this project, promising an experience that is sure to leave an impact.With its stellar cast, strong emotional core and relatable humour, The Great Shamsuddin Family is set to be a good holiday watch for families to enjoy together as it arrives on Jio Hotstar on December 12.

Kareena Kapoor

Celebrates 'Amma' Sharmila Tagore's 81st With Throwback Album

Veteran actress Sharmila Tagore turned 81 on Monday. Born on December 8, 1944, she has been a part of many memorable films including Anupama, Sawan Ki Ghata, An Evening in Paris, Safar, and several others.

Over the years, she has earned immense love and respect from the film industry and her fans.Naturally, her birthday led to a flood of wishes online. But family always comes first, so the most heartwarming message had to come from them. Kareena Kapoor took to Instagram to extend her birthday wishes to Sharmila, and her post was nothing short of adorable.

Bebo's Birthday Wish For Sharmila Tagore

Kareena shared a carousel of photos, with the first picture featuring Sharmila posing with Saif and little Jeh. The second captured a sweet moment of the daughter-in-law and mother-in-law walking together, and in the third, Sharmila was seen playing with her grandson again.

While the actress' caption read, "Happy birthday dearest Mother-in-law," she also added little notes to each photo. On the first picture, she wrote, "Happy birthday Amma." The second photo had the note, "Always trying to follow your footsteps," and the third one simply read, "All heart, always."

The comments section of the post was filled with wishes for the veteran actress. A user wrote, "Happy Birthday to a graceful, elegant lady." Another one said, "Happy Birthday to the beautiful soul, and a beautiful mother-in-law of Kareena Kapoor Khan. We love you Bebo."

Someone remarked, "Happy birthday to the most gracious, gorgeous and elegant lady!! She has aged like the finest wine on Earth." An individual commented, "Sharmila Ji is the most versatile heroine of the Golden Era."

Saba Pataudi Pens A Sweet Birthday Wish For Mom

Saba Pataudi shared a series of photos featuring her mom's throwback moments, family pictures, and a few frames of her posing with her mother, Sharmila Tagore on Instagram. Her caption was long, warm, and full of love. She wrote, "Diva to many, mother to us.

Moments and memories, treasured so much! A journey of a lifetime, growing up with you, learning the ropes, and surviving each other too!" She concluded her caption with, "With love and blessings, wishing you the best of health. Happiest Birthday Ammu! Love you always and forever."

Her comment section, too, was filled with love, with fans pouring in wholesome birthday messages for the veteran actress.

Farah Khan And Dilip Join 'Mangal Lakshmi' For Special Episode: 'Kitchen Is Guaranteed To Get Garam'

With her iconic humour and trademark spice, filmmaker Farah Khan joins Colors' television series 'Mangal Lakshmi' alongside internet favourite Dilip for a special episode where the kitchen turns into a lively fusion of dance and offbeat cooking tasks. In the ongoing track, the Pehla Swaad competition hits its most crucial stage with the Ticket to Finale challenge, where Bhabhiji (Neelu Waghela) as the new head chef pushes Mangal and Saumya into unexpected cooking tests. As Farah and Dilip introduce a thrilling 'jodi challenge', Saumya teams up with Adit, leaving Mangal to face the heat alone. And now, with the finale within reach, will Mangal be able to deliver a dish that not only wins the judges' hearts but seals her place in the competition?

Shooting for a special episode of COLORS' Mangal Lakshmi, Farah Khan said, "Arre bhai, jab kitchen ka maha-yudh ho raha ho Mangal Lakshmi mein, mujhe toh aana hi tha! I'm super excited to judge the 'Pehla Swaad' ticket-to-finale challenge — yahan khaane ka taste bhi test hoga aur contestants ka patience bhi. With my full-on Farah-tadka, thodi masti, thoda masala, and my cook Dilip joining the madness, the kitchen is guaranteed to get garam. Mangal aur Saumya dono ko mile surprises aur shocks, but who plates up the real winner's swaad, that you'll have to watch. All I can say is, this episode serves flavour, fun, and full-on fireworks."

Deepika Singh spoke about sharing screen space with Farah Khan in 'Mangal Lakshmi'. She said, "Mangal Lakshmi is at a phase where the pulse of the story is a woman finally rising for herself and for the business she built alongside other women; and the audience has showered a lot of love to the show throughout Mangal's journey. That's why creating a special Pehla Swaad episode with Farah Khan is a landmark moment, because the legend stands for everything my character aspires to. We've all admired her work, and having her on set instantly lifted the energy of an already thrilling challenge. Performing the cooking-and-dance act and then hearing her genuine words of encouragement is something I'll cherish my entire life."

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna Wanted The Show Extended: 'Request Karta Tha Confession Room Mein...'

Gaurav Khanna is over the moon after winning Bigg Boss 19! Last night, during the grand finale, Salman Khan handed him the trophy, while Farrhana Bhatt was announced as the first runner-up. Now, after winning Bigg Boss 19, Gaurav Khanna has shared that he wanted the show to continue longer. He revealed that he would request Bigg Boss for at least a one-week extension as he wanted to celebrate his birthday (on December 11), with the entire nation.

Gaurav Khanna Reveals He Wanted Bigg Boss 19 To Continue Longer

In a video shared by JioHotstar on Instagram, Gaurav Khanna says, "To be honest, I am feeling a little sad because I wanted the show to extend a bit longer. I was really enjoying myself inside." He would tease his housemates by saying he wanted the show to continue, while they kept saying they wanted to go home and couldn't understand why he wanted to stay longer. He said that he really enjoyed his time in the BB house, and behaved exactly as he would in his own home. "I was doing all the things I do at home – wearing the clothes I want, repeating the clothes, washing dishes," he said.

Gaurav further added that people have seen him act in many shows, so he wanted to show his fans how he is in real life. "I didn't want to do anything that I wouldn't do in real life. I really liked spending 105 days inside. Now the only sadness is that leaving such a big house and going back to my small home will be a bit of a challenge as I enjoyed walking around," he said.

When asked about his plans after the show, Gaurav added, 'I missed my wife Akanksha, so I will take her out somewhere. And my birthday is coming on the 11th, and I used to request Bigg Boss in the confession room to please extend the show by one week because I wanted to celebrate my birthday with all of India on Bigg Boss. But it's okay."

Gaurav Khanna won Bigg Boss 19, while Farrhana Bhatt emerged as the first runner-up, followed by Pranit More, Tanya Mittal and Amaal Mallik.